A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 08 जून, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 276, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भारतीय अर्थशास्त्रियों का पतन उनकी अपनी ही देन है

एम. आर. पई

यदि आज भारतीय राजनेता की छवि अत्यंत निराशाजनक हो गई है, तो भारतीय अर्थशास्त्री की छवि भी उससे प्रतिस्पर्धा करती हुई दिखाई देती है। भारतीय अर्थशास्त्रियों के अग्रणी विद्वानों में से एक, प्रोफेसर सी. एन. वकील, को भारतीय आर्थिक संघ के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में एकत्रित अर्थशास्त्रियों से यह अपील करनी पड़ी कि वे अपने आचरण का ध्यान रखें ताकि अपने पेशे की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रख सकें। उन्होंने कहाः 'यह अत्यंत दुखद स्थिति है कि आर्थिक मामलों में किसी व्यक्ति की योग्यता का आकलन इस आधार पर किया जाए कि वह राजनीतिक या अवसरवादी दबावों के बीच अपने विचारों पर कितना दृढ़ रहता है या कितना डगमगा जाता है। आर्थिक योग्यता के मानदंड स्वयं इस पेशे के भीतर निर्धारित होने चाहिए, बाहर से नहीं। यही वह क्षेत्र है जहाँ एक सशक्त आर्थिक संघ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सुरक्षा-कवच बन सकता है। '

राजनेता अपने ही कार्यों के कारण सम्मान खोते हैं। उसी प्रकार भारतीय अर्थशास्त्रियों की प्रतिष्ठा में आई गिरावट भी उनके अपने ही आचरण का परिणाम है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के युग ने अर्थशास्त्रियों को एक नया अवसर प्रदान किया था। वे अर्थशास्त्र के उपकरणों का उपयोग करके देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकते थे और जनता के सामने एक उपयोगी भूमिका निभा सकते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवसर खो दिया गया।

कई अर्थशास्त्रियों ने अपने आर्थिक ज्ञान और उपकरणों का उपयोग स्पष्ट रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया और इस प्रक्रिया में उन पेशेवर मानकों का त्याग कर दिया जो उनके पेशे की पहचान होने चाहिए थे। यह धारणा व्यापक है कि अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक पदों के आकर्षण में फंस गए हैं और सरकारी संरक्षण के मक्खन को अपने शोध की रोटी पर लगाने की अनुमति दे बैठे हैं।

यह कॅरियरवाद इतनी दूर तक बढ़ गया है कि आज अर्थशास्त्रियों के बीच भी किसी ऐसे पूर्व शिक्षाविद् का नाम लिया जाए जो अब सरकारी सत्ता में है, तो उसका स्वागत अक्सर व्यंग्य और उपहास से किया जाता है। कई अर्थशास्त्रियों ने एक से अधिक अवसरों पर जनता की नजर में यह सिद्ध कर दिया है कि उनका वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों से कोई विशेष संबंध नहीं है। यह दो प्रकार से सामने आया।

कुछ अर्थशास्त्री किसी समय सरकार की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखाई दिए। बाद में वही नीतियाँ व्यवहार में असफल सिद्ध हुईं। जब जनता का रुझान सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो गया, तब वही अर्थशास्त्री उन नीतियों की आलोचना करने लगे जिनका वे पहले समर्थन कर चुके थे। इसका एक प्रमुख उदाहरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना है।

सरकारी प्रकाशन 'द्वितीय योजना के निर्माण से संबंधित दस्तावेज' में अर्थशास्त्रियों के पैनल और योजना आयोग के विचार संकलित हैं.।प्रोफेसर बी. आर. शेनॉय को छोड़कर, जिनकी असहमति बाद में भविष्यवाणी जैसी सही सिद्ध हुई, लगभग सभी ने योजना का समर्थन किया था। बाद में जब यह योजना देश के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई, तो उन्हीं में से कुछ अर्थशास्त्री उसकी तीखी आलोचना करने लगे। जनता के लिए निष्कर्ष निकालना आसान था। या तो इन अर्थशास्त्रियों ने सरकार को प्रसन्न करने के लिए योजना का समर्थन किया था और जनता के असंतोष के बाद ही आलोचना करने का साहस जुटाया, अथवा वे केवल सैद्धांतिक विद्वान थे जिन्हें वास्तविक परिस्थितियों की कोई समझ नहीं थी।

अर्थशास्त्रियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का दूसरा तरीका तब सामने आया जब उन्हें सत्ता के पदों पर बैठकर आर्थिक मामलों का संचालन करने का अवसर मिला। आर्थिक विषयों पर लंबे-लंबे व्याख्यान देने वाले कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने मंत्रालयों और विभागों का ऐसा बुरा हाल किया कि उनकी सारी विद्वत्ता संदेह के घेरे में आ गई। संयम की कमी भी जनता की नजर में भारतीय अर्थशास्त्री की गिरती प्रतिष्ठा का एक कारण है। इसका एक उदाहरण औद्योगिक लाइसेंसिंग पर हाल ही में आई रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट एक मूल्यवान विश्लेषण थी, लेकिन विश्लेषण की प्रक्रिया में ऐसा आभास दिया गया कि यह किसी एक औद्योगिक घराने पर हमला है, जिससे इसकी उपयोगिता कम हो गई। लोकनीति का मूल सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति या संस्था को तब तक विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक उसने देश के कानूनों का उल्लंघन न किया हो। और यदि उसने कानून तोड़ा है, तो उसके लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, एक आधिकारिक दस्तावेज़ में 'मारवाड़ी पूंजी ', 'गुजराती पूंजी' और 'पारसी पूंजी' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसे समय में जब उप-राष्ट्रीयता के बढ़ते प्रभाव के बीच राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पहले से अधिक है, पूँजी के स्वामित्व के सामुदायिक पहलुओं पर जोर देना रिपोर्ट के लेखक की एक गंभीर भूल थी।

आर्थिक समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को त्यागने का एक और स्पष्ट उदाहरण बैंक राष्ट्रीयकरण पर चार अर्थशास्त्रियों की तथाकथित रिपोर्ट में देखा जा सकता है। यह वास्तव में कोई शोध दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक ऐसा पैम्फलेट है जो उसके लेखकों के बैंक राष्ट्रीयकरण के पक्ष में वैचारिक झुकाव पर आधारित है।

अन्य नागरिकों की तरह अर्थशास्त्रियों को भी अपनी कोई भी विचारधारा रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें यह सावधानी रखनी चाहिए कि वे अपनी वैचारिक मान्यताओं को वैचारिक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करें, न कि शोध दस्तावेज़ के रूप में। हाल के सम्मेलन में प्रोफेसर वकील ने उचित ही कहाः 'हमें याद रखना चाहिए कि अर्थशास्त्री संत नहीं होते। उनके भी अपने कॅरियर संबंधी लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सभी अर्थशास्त्रियों के सपने केवल विद्वत्ता के क्षेत्र तक सीमित नहीं होते।

इसलिए किसी भी अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण को हर परिस्थिति में अंतिम आर्थिक दृष्टिकोण मान लेना उचित नहीं है। इसी कारण यह सभी अर्थशास्त्रियों का विशेष दायित्व है कि वे एक-दूसरे के विचारों की कठोर और निष्पक्ष आलोचना करें। तभी जनता यह समझ सकेगी कि कब और कहाँ कोई अर्थशास्त्री नीति-निर्माण की दुनिया में प्रवेश करते समय अपने गैर-आर्थिक पूर्वाग्रहों या अन्य प्रभावों के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहा है। यह सर्वविदित है कि सत्ता में बैठे लोग हमेशा ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं जो उनके विचारों और नीतियों का समर्थन करें। कई भारतीय अर्थशास्त्रियों ने स्वयं राजनेता बनने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप वे न तो अच्छे राजनेता बन सके और न ही अच्छे अर्थशास्त्री। यदि अर्थशास्त्री कोई आचार-संहिता नहीं अपनाते, अपनी सोच की स्वतंत्रता को स्थापित नहीं करते और अपनी बौद्धिक ईमानदारी तथा नैतिकता को बनाए नहीं रखते, तो वे अपने कर्तव्य की उपेक्षा के लिए जनता के रोष का सामना करेंगे।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

उज्जैन जिले के नारायणा और धार जिले के अंका-झंका में बनाएंगे तीर्थ

भागवत कथा श्रवण से मिटते हैं दुःख-दर्द संसार का होता है कल्याण : मुख्यमंत्री यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्रीमद्भागवत कथा का पुण्य-प्रताप ऐसा है कि इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के दुःख-दर्द दूर हो जाते हैं। भागवत कथा श्रवण से कष्टों का शमन होता है और पूरे संसार का कल्याण होता है। इस कथा का श्रवण मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। ये समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं और सबके जीवन में सद्भाव एवं आत्मिक शांति का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा मानव जीवन को धर्म के मर्म एवं नैतिकता का भान कराती है। यह मनुष्य को उसके कर्तव्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञानामृत है। भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों और उनके संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने में भागवत गीता कथा एक पवित्र माध्यम है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में एक से सात जून तक हुई श्रीमद्भागवत कथा के समापन समारोह को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कथा समापन समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट थे, परंतु उन्होंने अपने कष्टों से इतर कुशासन (कंस) का अंत किया। वे सदैव धर्म मार्ग पर बने रहे। उन्होंने समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं से कहा कि वे गीता के संदेश को अपने जीवन में भी अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण ने लीलाएं कीं, वहां-वहां हमारी सरकार भव्य श्रीकृष्ण तीर्थ बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि उज्जैन जिले के नारायणा गांव और धार जिले के अंका-झंका माताजी परिसर में भव्य श्रीकृष्ण तीर्थ बनाया जायेगा। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्राम टंकारिया पंथ से लेपड़ तक एवं इसी गांव से रानापुर फाटक तक पक्की सड़क बनाई जायेगी।

उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते का सवाल नहीं

- किम की बहन ने दिखाए तेवर, बोलीं- अमेरिका सपना देख रहा

प्योंगयांग (एजेंसी)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर किसी समझौते की संभावना से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त मैसेज देते हुए उत्तर कोरिया की सीनियर अधिकारी किम यो ने कहा कि परमाणु शक्ति के रूप में हमारी स्थिति पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम अमेरिका को बताना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा।

सुप्रभात

गर्मी की शांत दुपहरी है
बाहर इक्का-दुक्का आवाजें हैं
दो गृहणियों के आपस में बातें करने
के अस्फुट स्वर हैं
दूसरे लोक से आते हुए
अभी-अभी एक स्कूटर गुज़र कर गया है
दूर रेडियो पर सुगम संगीत में गायिका
ऊबी-डूबी आवाज़ में गा रही है
सावन आया तुम नहीं आए
छत पर धीमी आवाज़ में घूमता पंखा है
दीवाल पर टिक-टिक करती घड़ी है
बेटा-बहू काम पर गए हैं
पत्नी दूसरे कमरे में दुखती कमर
सीधी कर रही है

काम कुछ शेष नहीं
नाम कुछ होना नहीं है
यही समय है चुपचाप चले जाने का।

- चंद्रशेखर साकल्ले

वाराणसी में शहर से बाहर शिफ्ट होंगी मांस-मछली की दुकानें

- सावन से पहले नगर निगम का अहम फैसला, सरकार भी ऐक्टिव

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी नगर निगम ने मांस और मछली की सभी दुकानें शहर की सीमा से बाहर ट्रांसफर करने का फैसला किया है। सावन से पहले नगर निगम ने यह कदम शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की मंशा से उठाया है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने रविवार को बताया कि महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को मैदागिन स्थित टाउन हॉल भवन में बैठक हुई। इस बैठक में मांस और मछली की दुकानों को शहर से बाहर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में वाराणसी के विकास को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मौजूद नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सदन को बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में पांच जगहों का चयन किया जा चुका है और यह सभी स्थान शहर की बाहरी सीमाओं के करीब हैं।

- एक का सिर मुंडवाया, जूते की माला पहनाकर परेड निकाली

बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फूट रहा लोगों का गुस्सा

दूसरा पुलिस से बचने साड़ियों में छिपा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। कोलकाता में रविवार को गिरफ्तार टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। वहीं, सोशल मीडिया पर दो और वीडियो वायरल हैं। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें पुलिस से बचने के लिए एक नेता साड़ियों के नीचे छिपा मिला। दूसरा वीडियो नवादा का है। इसमें कटमनी वसूल करने वाले एक नेता का लोगों ने पहले सिर मुंडवाया। फिर जूते-चप्पल की माला पहनाकर उसकी परेड निकाली। ये वीडियो बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी एक्स पर शेयर किए हैं।

रिश्वत लेने के आरोप में नेता का सिर मुंडवाया

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हावड़ा के अमरदाहा गांव में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता सन्यासी मन्ना का सिर मुंडवाकर उन्हें जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। ग्रामीणों का आरोप है कि वह सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मन्ना को भीड़ से छुड़ाया।

गिरफ्तार टीएमसी पार्षद की गाड़ी पर अंडे फेंके

कोलकाता में गिरफ्तार टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। पाटुली थाने के बाहर भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कोलकाता नगर निगम के वार्ड-101 के पार्षद दासगुप्ता को शनिवार को उनके सहयोगी सौरव घोष के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर रंगदारी, धमकी, जबरन घुसपैठ और आग लगाने की कोशिश समेत कई आरोप हैं। स्थानीय वकील परमिता डे ने शिकायत में आरोप लगाया है कि दासगुप्ता ने घर में लीगल चैंबर खोलने के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे।

बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे अवैध प्रवासी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हकीमपुर चेकपोस्ट पर इन दिनों अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ जुट रही है। ये लोग खुद अपनी पहचान बताकर बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि, सीमा सुरक्षा बल उन्हें सीधे सीमा पार भेजने के बजाय बायोमीट्रिक और अन्य पहचान पत्र लेकर बंगाल में बनाए गए होल्डिंग सेंटरों में भेज रही है। हकीमपुर बॉर्डर पर वेरिफिकेशन सेंटर पर रोजाना करीब 200 से 300 लोग वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से कई लोग सालों पहले अवैध रूप से भारत आए थे और अब बदलते हालात के बीच अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई लोगों के पास भारतीय दस्तावेज हैं, लेकिन बांग्लादेशी पहचान संबंधी कागजात नहीं हैं।

बंगाल में रोज 200-300 लोगों का वेरिफिकेशन,बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव

प्रवासी ने कहा- भारत में रह नहीं पा रहे, बांग्लादेश जा नहीं सकते

मुंबई में रह रहे मोहम्मद अख्तर शेख ने बताया कि वह 22 साल पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। उनके पास भारतीय आधार कार्ड है, लेकिन बांग्लादेश का कोई दस्तावेज नहीं है। उन्हें डर है कि अब वे न बच्चों के साथ रह पाएंगे और न ही बांग्लादेश जा सकेंगे।' इसी तरह, 20 साल पहले मुर्शिदाबाद के जलंगी बॉर्डर के रास्ते भारत आए इस्लाम सरदार बात करते-करते रोने लगे।

जितने वेरिफिकेशन हुए, होल्डिंग सेंटर में उससे कम ही गए

गृह मंत्रालय के निर्देश पर बंगाल में 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर 24 परगना जिले के तेतुलिया में एक होटल को होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक, इन 11 सेंटरों में फिलहाल एक हजार से कम लोग हैं। यहां भोजन, डॉक्टर और बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बीच, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने बीएसएफ पर अवैध प्रवासियों को उनके देश की सीमा में धकेलने की कोशिश का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि पिछले 24 घंटे में ऐसी 10 कोशिशें रोकी गई हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 08 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

बस में बैठकर गांव पहुंचे कलेक्टर नामदेव, बच्चों संग खेला वॉलीबाल

पंगत में किया भोजन और खाट पर ही सो गए, सादगी देख जमकर हो रही तारीफ

मंडला (नप्र)। जिले के अंदरूनी गांव 'दाढ़ी' में जिले के मुखिया कलेक्टर रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और उन्हें हल कराने पहुंचे थे। यहां उन्होंने एसपी, जिला पंचायत सीईओ संग पंगत में बैठकर भोजन किया और रात में खुले आसमान के नीचे खाट पर मच्छरदानी लगाकर सो गए। साहब का यह रूप देख ग्रामीण अचंभित और गद्गद हो गए। आईएएस राहुल नामदेव की तारीफ में लोग कसीदे पढ़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश में तस्वीर कुछ बदली-बदली सी नजर आ रही है। एसी चैंबरों में बैठकर जिले का शासन चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी अब गांव में चौपाल लगाते दिख रहे हैं। ऐसा ही नजारा प्रदेश के मंडला जिले से सामने आया। कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश रघुवंशी

सहित तमाम प्रशासनिक अमला यहां रात्रि चौपाल लगाने पहुंचा था। सबसे अहम बात अधिकारी हूटर बजाती लालबत्ती एसी गाड़ियों के बजाय बस दाढी गांव से पहुंचे थे।

खुलेआसमान के नीचे खाट पर मच्छरदानी लगाकर सो गए- दरअसल एमपी के मंडला जिले में मवई के ग्राम दाढ़ी में कलेक्टर कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश रघुवंशी और ने दाढ़ी में प्रशासन आपके द्वार की कल्पना को साकार किया। उन्होंने यहां शाम को चौपाल लगाकर फर्श पर बैठकर गांव वालों से संवाद किया। उनकी समस्याएं और परेशानी सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। रात में प्रशासन की तरफ से यहां सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने प्रोटोकॉल छोड़कर जमीन पर सादगी से भोजन किया और खुले आसमान के नीचे मच्छरदानी लगाकर रात गुजारी।

सुबह युवाओं संग वॉलीबॉल खेलते नजर आए अधिकारी- सुबह मच्छरदानी से निकलकर अधिकारी गांव में युवाओं के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए। कलेक्टर-एसी जैसे अधिकारियों को अपने बीच देख युवाओं में भारी उत्साह रहा। इसके बाद, पूरा प्रशासनिक अमला गलियों में पैदल निकल पड़ा। उन्हें देख बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा भी इस अभियान से जुड़ते चले गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान किया।

राजनीति ईमानदार होगी तभी गांधी - लोहिया के सपने साकार होंगे: रघु ठाकुर

ग्वालियर। समाजवादी चिंतक व लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक रघु ठाकुर ने कहा है कि राजनीति जब ईमानदार होगी तब महात्मा गांधी और लोहिया के विचार साकार होंगे। जनता के पास जाकर उसका दिल जीतने और सादगी को आचरण में उतारने पर ही देश की राजनीति बदलेगी।

रघु ठाकुर ग्वालियर में लोसपा के दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे। बघेल छात्रावास में यह शिविर दो दिन के इस शिविर में पार्टी के विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उद्घाटन सत्र में पार्टी के संगठन निर्माण पर चर्चा हुई। दूसरे सत्र में रघु ठाकुर के वक्तव्य का विषय था दुनिया की समस्याओं का हल गांधी एवं लोहिया के विचारों में है। रघु ठाकुर ने कहा कि देशवासियों के मस्तिष्क में चेतना पैदा करने के लिए एक ऐसे सांस्कृतिक अभियान की जरूरत है जो लोगों को गुलाम मानसिकता को समाप्त करने, जातिवाद खत्म करने और हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि समाजवादी होने का मतलब समय पर विरोध करना है। बिना तकलीफ सहे परिवर्तन का सपना देखना खुद को धोखा देना है।

रघु ठाकुर ने नीट पेपर लीक होने के मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि गुनाहगार केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के बजाय ' मन की बात' में बिहार के सत्तू और आम की बात की जा रही है। जबकि पेपर लीक प्रकरण में सत्रह बच्चों ने आत्महत्या कर ली है और परीक्षा में पास होने वाले और न होने वाले सबके हिस्से में बेरोज़गारी आई है।

काकरोच जनता पार्टी की तुलना अन्ना आंदोलन से करते हुए रघु ठाकुर ने कहा तब जिस टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले और जनलोकपाल के मुद्दे पर वह आंदोलन हुआ था उसका हासिल क्या रहा।

संक्षिप्त समाचार

इंजीनियर के लॉकरों ने उगले 2 करोड़ कैश

- ओडिशा में 5 मल्टीस्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लॉट

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बेहरा कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी में पदस्थ हैं। उनका 1999 में जूनियर इंजीनियर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ था। तब सैलरी 6 हजार रुपए थी। ओडिशा विजिलेंस को बेहरा के पास आय से ज्यादा

संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद भुवनेश्वर के विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) के सर्च वारंट के आधार पर विजिलेंस ने शुक्रवार को भुवनेश्वर, जाजपुर, बारिपदा और कंधमाल जिले के कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 5 बहुमंजिला इमारतें, 13 प्लॉट, सोने के गहने और बैंक लॉकरों से करीब 2.4 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। सभी संपत्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाइयों में एक माना जा रहा है।

भुवनेश्वर में चार बहुमंजिला आलीशान मकान

भुवनेश्वर के 4 इलाकों के अलावा जाजपुर जिले के धर्मशाला स्थित पैतृक घर, रिश्तेदारों के आवास, सरकारी क्वार्टर और ऑफिस में भी तलाशी ली गई। कार्रवाई में 2 एडिशनल एसपी, 5 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर और बड़ी संख्या में अन्य अधिकारियों को लगाया गया। जांच में अब तक पांच बड़ी इमारतों का पता चला है।

पार्टी का विलय कीजिए या किनारे लग जाइए !

- बीजेपी ने उपेन्द्र कुशवाहा को दे दिया सख्त 'मैसेज'

पटना (एजेंसी)। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में टिकट क्यों नहीं दिया। एनडीए के सभी 9 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब 8 जून को कोई चमत्कार हो जाए तो अगर बात है, लेकिन फिलहाल दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में पड़ गया नजर आ रहा है। छह महीने के अंदर किसी सदन के

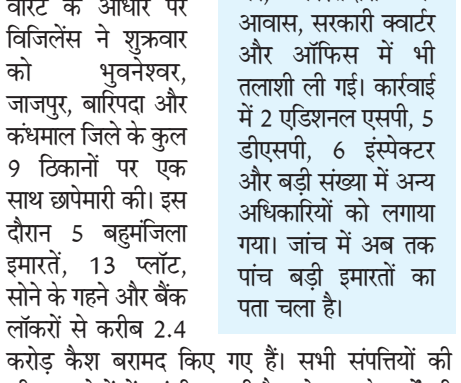

सदस्य बनने की संभावना अब धूमिल होती दिख रही है। अभी जो सामने तस्वीर है उसके हिसाब से कुछ दिनों में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि भाजपा अब आर-पार के मूड में है। मार्च में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब भाजपा ने उपेन्द्र कुशवाहा के सामने शर्त रखी थी कि यदि वे अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भाजपा में विलय कर लेते हैं तभी उनको राज्यसभा में और दीपक प्रकाश को विधान परिषद में भेजा जाएगा। उपेन्द्र कुशवाहा राज्यसभा में चले भी गये। भाजपा ने उनकी जीत को सुनिश्चित जीत के लिए चौथा उम्मीदवार बनाया था। कुशवाहा के लिए भाजपा ने खुद अपने उम्मीदवार शिवेश राम को पांचवां उम्मीदवार बना कर चुनौतियों से लड़ने के लिए छोड़ दिया था। भाजपा की इस दरियादिली के बाद भी रालोमो का भाजपा में विलय नहीं हुआ।

नीट पेपर लीक के बाद बदलेगा एनटीए का सिस्टम

एक्सपर्ट्स सवाल तैयार तो करेंगे, पर पता नहीं होगा किस एग्जाम के लिए किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट 2026 पेपर लीक और सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ियों के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, एनटीए ऐसा नया सिस्टम बनाने पर काम कर रही है, जिसमें सवाल तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा कि वह किस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। नई योजना के तहत अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट्स केवल सवाल तैयार करेंगे। इन सवालों को एक बड़े डिजिटल बैंक में रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसमें करीब 10 हजार सवाल हो सकते हैं। बाद में टेक्नीक की मदद से इन सवालों से फाइनल एग्जाम पेपर तैयार होगा। वहीं, शनिवार को अखबार के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा- पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। मंत्री जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।

रिजिजू बोले- शिक्षा मंत्री पर सीधा आरोप हो तो इस्तीफा मांगिए

रिजिजू ने कहा कि लाखों छात्रों को नीट दोबारा देने की नौबत आई और सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ियों से भी परेशानी हुई। ऐसे मामलों में सरकार की जिम्मेदारी समस्या को ठीक करना है, न कि उससे बचना। उन्होंने भरोसा जताया कि उठाए गए कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री या उसके स्टाफ पर सीधे भ्रष्टाचार, रिश्वत या गलत काम का आरोप हो तो इस्तीफे की मांग जायज होती है।

एनटीए बोला- नीट री-एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ

नीट 2026 री-एग्जाम से पहले सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर पेपर लीक होने और सवाल पहले से मिलने के कई दावे किए जा रहे हैं। एनटीए ने इन सभी दावों को गलत और भ्रामक बताया है। एजेंसी का कहना है कि कुछ ठग गिरोह छात्रों और उनके परिवारों को गुमराह कर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित पेपर और लीक से जुड़े मैसेज पूरी तरह फर्जी हैं। एनटीए ने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। एजेंसी ने छात्रों से अफवाहों पर भरोसा न करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही, ऐसे फर्जी मैसेज और पोस्ट फैलाने वाले अकाउंट्स व चैनलों की पहचान की जा रही है।

सिस्टम को लोगों पर नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए

एनटीए से जुड़े अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे प्रश्नपत्र की जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचे। सिस्टम को लोगों पर नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए। पेपर लीक मामले में ट्रांसलेशन करने वालों की गिरफ्तारी के बाद एनटीए ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी बदलाव करना चाहती है। एजेंसी पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि वह करीब 85 फीसदी ट्रांसलेशन का काम एआई से कराने की योजना बना रही है। इसके बाद एक्सपर्ट्स सिर्फ यह जांचेंगे कि ट्रांसलेशन सही हुआ या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि कोशिश यह भी रहेगी कि ट्रांसलेशन करने वालों को यह जानकारी न हो कि वे किस परीक्षा के सवाल देख रहे हैं। वहीं, एनटीए इस समय 21 जून को होने वाले नीट यूजी री-टेस्ट की तैयारी भी कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ बदलाव अभी से लागू किए जा चुके हैं। इसके तहत नए सब्जेट एक्सपर्ट्स को जोड़ा गया है। साथ ही पेपर छपने के बाद उसके ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सिस्टम को और सुरक्षित बनाने पर भी काम चल रहा है।

घर के चूल्हे में फिर लगी 'महंगाई' की आग

- घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह तीन महीने में दूसरी बढ़ोतरी है, क्योंकि सरकारी ईंधन कंपनियां बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागत से जूझ रही हैं। दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये

हो गई है। यह नई दर 7 जून से लागू हो गई है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, मार्च में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसके चलते 7 मार्च को 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।

दूसरे ईंधनों की कीमतों में भी वृद्धि

एलपीजी की इस बढ़ोतरी के साथ ही अन्य ईंधनों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। मई के मध्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7.50 प्रति लीटर रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। सीएनजी की दर में करीब 6 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद तेल कंपनियां पेट्रोल पर 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33.60 रुपये प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं।

गौतम अडानी 1, मुकेश अंबानी 2

एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर

नई दिल्ली (एजेंसी)। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति बढ़कर 89.2 अरब डॉलर हो गई है। यह उन्हें एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलेनियर्स लिस्ट में यह जानकारी दी गई। अडानी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन को 87 अरब डॉलर के साथ तीसरा पायदान मिला है। सोन गुरुवार को जापानी निवेश फर्म के शेयरों में गिरावट से पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे।

हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद आई थी गिरावट

अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 में अडानी पर स्टॉक में हेरफेर और व्यापक धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि, भारतीय नियामकों ने पिछले साल इन दावों को खारिज कर दिया था। कहा था कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। उन्हें अमेरिका में भी आरोपों का सामना करना पड़ा था। ये अब समाप्त हो चुके हैं।

कानूनी चुनौतियों से उबर चुका है अडानी ग्रुप

अरबपति उद्योगपति ने पिछले महीने शेयरधारकों को लिखे अपने वार्षिक पत्र में कहा कि अडानी समूह अमेरिकी कानूनी चुनौतियों से उबर चुका है। ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा रहा है। इससे वह एआई आधारित विकास की बढ़ती मांग से फायदा उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के हालिया 24,930 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू की सफलता को निवेशकों का विश्वास बताया।

बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में रार

डीएमके-एएपी का बहिष्कार, बैठक से कर लिया किनारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में सीपीआई (एम) का प्रतिनिधित्व पार्टी के राज्यसभा नेता जॉन ब्रिटास करेंगे। हालांकि, केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगे आरोपों को लेकर पार्टी अभी भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले

से बताया कि सीपीआई (एम) के महासचिव एम.ए. बेबी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को पत्र लिखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उन टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिनमें केरल में सीपीआई (एम) और बीजेपी के बीच राजनीतिक समझ होने का संकेत दिया गया था।

गठबंधन की भावना के खिलाफ आरोप

लेटर की कॉपी इंडिया ब्लॉक के दूसरे हिस्सों के साथ भी शेयर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसे आरोप विपक्षी गठबंधन की सहयोग की भावना के खिलाफ हैं। लेफ्ट पार्टी ने कहा है कि वह इस मामले पर कांग्रेस से सफाई का इंतजार कर रही है। सीपीआई (एम) के सूत्रों ने कहा कि पार्टी को अभी तक कांग्रेस से कोई जवाब नहीं मिला है और उम्मीद है कि ब्रिटास मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे।

मुद्दे को लेकर दोनों दलों में विवाद

इस बातचीत में, बेबी ने चिंता जताई थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खरगे समेत कांग्रेस नेताओं के आरोप चुनावी आलोचना से कहीं आगे थे, जिससे बीजेपी को मिलकर चुनौती देने के लिए बने गठबंधन के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए। केरल विधानसभा चुनावों के बाद से ही यह मुद्दा दोनों पार्टियों के बीच विवाद का विषय रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्ष की एकजुटता को मजबूत करने की साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

- महिलाएं चलाती हैं पूरा बाजार, 500 साल पुराना इतिहास

अनोखा बाजार, यहां पुरुषों के लिए नो एंट्री!

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में रहा है। लेकिन यहां की राजधानी इंफाल के एक बाजार के बारे में आप नहीं जानते होंगे। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर सभी दुकानें केवल महिलाएं ही रन करती हैं। इनकी संख्या भी कोई सौ-दो सौ नहीं है, बल्कि हजारों में है। यह महिलाएं, सब्जियों, मछली, मसालों, कपड़ों, हाथ से बने सामान, ज्वैलरी और घर के सामान की अन्य दुकानों पर बैठती हैं। यह सभी दुकानें सुबह-सुबह खुल जाती हैं और देर रात तक सामानों की खरीद-फरोख्त चलती रहती है।

5000 से अधिक महिला विक्रेता

अनुमान के मुताबिक आज इंफाल के इस बाजार में 5,000 से अधिक महिला विक्रेता काम करती हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाजार का मैनेजमेंट पूरी तरह से महिलाएं ही संभालती हैं। इनमें से कई परिवारों में पीढ़ियों से स्टॉल विरासत में मिले हैं। कई दुकानें तो ऐसी हैं, जिन्हें मां ने अपनी बेटियों को सौंप दिया है। इस तरह यह काम पीढ़ी-दर-पीढ़ी होता चला आ रहा है।

युद्ध से भी कनेक्शन

इसे चलाने वाली महिलाएं ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाएं भी निभाती रही हैं। मणिपुरी महिला व्यापारियों ने मशहूर नूपी लान, या महिला युद्धों हिस्सा लिया था। यह युद्ध 1904 और 1939 के दौरान हुए थे, जब महिलाओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों और आर्थिक शोषण का विरोध किया। इसलिए बाजार न केवल एक कॉमर्शियल हब के तौर पर विकसित हुआ बल्कि सामूहिक राजनीतिक सक्रियता के लिए भी जाना गया।

इसे कहते हैं मां का बाजार

इस बाजार का नाम है, इमा कीथल। हिंदी में कहें तो मां का बाजार। माना जाता है कि यह सभी दुकानें 500 साल पुरानी हैं और एशिया में महिलाओं के सबसे बड़ी मार्केट के रूप में जानी जाती हैं। मणिपुर सरकार और विभिन्न ऐतिहासिक अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि इस बाजार का इतिहास 16वीं सदी के राजा खागेम्बा से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि बाजार का विकास आंशिक रूप से पुराने मणिपुरी 'लल्लूप-कबा' सिस्टम के चलते हुआ। इस सिस्टम में कई पुरुषों को समय-समय पर सेना में काम करने या जबरन मजदूरी के लिए भेजा जाता था। पुरुषों की गैरमौजूदगी में महिलाएं व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां चलाती थीं। समय के साथ, इस पर महिलाओं का ही पूरा नियंत्रण हो गया।

टीटी नगर स्टेडियम से गूंजा फिट इंडिया का संदेश

भोपाल (नप्र)। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में रविवार सुबह फिटनेस और जागरूकता का उत्साह देखने को मिला। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम पहुंचकर संडे ऑन साइकिल अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान हजारों की संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों, सामाजिक संगठनों, स्कूली विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने साइकिल रैली में भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।

मंत्री सारंग ने किया साइकिल रैली का शुभारंभ

कार्यक्रम का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोगों को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। सुबह से ही टीटी नगर स्टेडियम परिसर में युवाओं और नागरिकों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। हाथों में फिट इंडिया और हेल्थ अवेयरनेस के संदेश लिए प्रतिभागियों में विशेष उत्साह दिखाई दिया।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में फिट इंडिया मूवमेंट को जनआंदोलन का स्वरूप दिया गया है। संडे ऑन साइकिल उसी संकल्प का हिस्सा है, जिसके माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल और व्यस्त जीवन में फिटनेस को दिनचर्या का हिस्सा बनाना बेहद आवश्यक है और साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए सबसे सरल एवं प्रभावी माध्यमों में से एक है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि साइकिल केवल फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत संदेश देती है। इससे प्रदूषण कम होता है और व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे मोबाइल और स्क्रीन टाइम से बाहर निकलकर खेल, योग, साइकिलिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़ें। उन्होंने बताया कि संडे ऑन साइकिल अभियान आज केवल भोपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के विजन को साकार करने के लिए यह पहल जनभागीदारी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, फिटनेस क्लबों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों ने भाग लेकर फिट इंडिया के संदेश को मजबूती प्रदान की।

कार्यक्रम के दौरान पूरे टीटी नगर स्टेडियम क्षेत्र में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। प्रतिभागियों ने साइकिल रैली निकालकर फिट रहो, स्वस्थ रहो और फिट इंडिया जैसे संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। मंत्री श्री सारंग ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं और मध्यप्रदेश सरकार युवाओं को खेल एवं फिटनेस से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

इस आयोजन ने राजधानी भोपाल में फिटनेस और जनजागरूकता का सकारात्मक संदेश देने के साथ युवाओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया।

खाद्य सुरक्षा आज की बड़ी जरूरत : मुख्यमंत्री

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री ने की खाद्य गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहने की अपील

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर-पोषण से जुड़ा विषय है। 'विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस' की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए, हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें।

मुख्यमंत्री ने महिला फुटबॉल टीम को दी बधाई

एसएएफएफ वुमेन चैपिंयनशिप-2026 में भारत ने बांग्लादेश को दी शिकस्त

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप-2026 जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह शानदार विजय भारत की बेटियों के साहस, प्रतिभा और टीम भावना का प्रतीक है। भारतीय टीम की यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। पूरी टीम हार्दिक बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।

उल्लेखनीय है कि गोवा राज्य के मडगांव में 25 मई से 6 जून की अवधि में हुई इस चैम्पियनशिप में भारत की सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए भारतीय महिला खिलाड़ियों को बधाई दी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 18 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की चहुँओर प्रशंसा हो रही है।

4 महीने की प्रेग्नेंट महिला की संदिग्ध हालत में मौत

5 महीने पहले परिजनों की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज, कलाई पर कट का गहरा निशान

भोपाल (नप्र)। बैरागढ़ इलाके में रहने वाली नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। जबकि पुलिस शुरुआती तौर पर आत्महत्या मानकर मामले की जांच कर रही है। महिला ने 5 महीने पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। सुसाइड से पहले उसका पति से अन्य महिला से बात करने को लेकर विवाद हुआ था। मृतक को 4 महीने की प्रेग्नेंसी थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

25 वर्षीय भारती सोलंकी पत्नी विक्की सोलंकी संजय नगर बैरागढ़ की रहने वाली थी और हाउस वाइफ थी। भारती ने 5 महीने पहले विक्की से लव मैरिज की थी। हालांकि परिजन इस शादी के खिलाफ थे लेकिन भारती ने शादी कर ली। महिला गर्भवती थी और सुसाइड से 2 दिन पहले डॉक्टर से रूटीन चेकअप भी कराया था। शादी से पहले तक भारती एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। विक्की और उसकी मुलाकात इसी दौरान हुई थी। घटना शनिवार रात की है, जबकि पोस्टमार्टम रविवार की सुबह किया गया है।

घरेलू सिलेंडर 29 रुपया महंगा

ग्वालियर-उज्जैन में 1000 पार, भोपाल में 947, इंदौर में 970, जबलपुर में 919 में मिलेगा

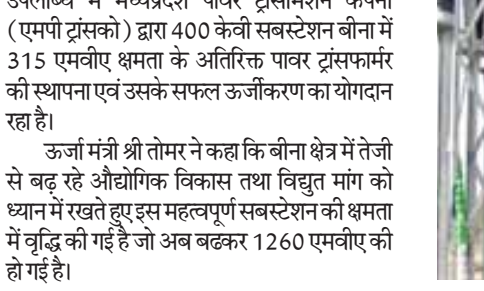

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें आज रविवार (7 जून) से लागू हो गई है। भोपाल में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 918.50 से बढ़कर 947.50 हो जाएगी। 5 बड़े शहरों में ग्वालियर में कीमत 1 हजार रुपए पार हो गई है। ग्वालियर में 1025 और उज्जैन में 1001 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। इंदौर में अब रेट 970 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए हो गए हैं।

मोरटक्का पुल पर जाम, आंधी से ऑटो पलटा

सीहोर में सोलर पैनल सेटअप उखड़ा, मलबे में दबा मासूम, 35 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में प्री-मानसून का दौर रविवार को भी जारी था। खंडवा जिले के मोरटक्का में नर्मदा नदी पर बने पुल पर तेज आंधी और बारिश के दौरान जाम की स्थिति बन गई। इंदौर-खंडवा हाईवे के इस पुल का वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज हवा के बीच एक ऑटो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में करीब एक घंटे तक बारिश हुई।

वहीं सीहोर में आंधी ने तबाही मचा दी। एक मोबाइल दुकान के पास लगा सोलर पैनल सेटअप, शेड और बिजली का खंभा पिलर सहित उखड़कर नीचे गिर गया। आसपास के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे में कई मकानों की दीवारें और टीन शेड जमींदोज हो गए।

मलबे में दबा मासूम, लोगों ने बचाई जान- इस दौरान कलीम मैकेनिक का बेटा मलबे की चपेट में आ गया। दीवार और शेड गिरने से बच्चा मलबे के नीचे दब गया। गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर मलबा हटाया। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।

मौसम विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरदा, सीहोर, देवास और खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने के साथ 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है।

वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, आगर-मालवा, खरगोन, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, दमोह समेत कई जिलों में बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दोपहर करीब 3 बजे जबलपुर और सीहोर में भी बारिश दर्ज की गई।

साथ ही शाम के समय बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली समेत पूर्वी और दक्षिणी जिलों में मौसम बदला रहने का अनुमान है।

मप्र में 20 जून तक मानसून की एंट्री संभव- केरल के रास्ते देश में प्रवेश कर चुका मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा तक पहुंच चुका है। जल्द महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 20 जून से पहले होने की संभावना है।

सीहोर में आंधी-बारिश, सब्जी मंडी से सड़क पर बहीं सब्जियां

सीहोर में रविवार को आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के पीछे बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली का असर बताया जा रहा है। सीहोर के शासकीय कृषि कॉलेज स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एस.एस. तोमर के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।नगरीय क्षेत्र में हवाओं की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि एक इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया।

आंधी-बारिश के बीच प्रदेश में गर्मी का असर भी बना हुआ है। शनिवार को नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सागर में 41.5, दतिया में 41.4, खजुराहो और दमोह में 41, गुना में 40.6 तथा खंडवा में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कुछ जिलों में हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया है।

सब्जी से सड़क पर बहीं सब्जियां- तेज बारिश और आंधी का असर शहर की सब्जी मंडी पर भी देखने को मिला। सब्जी मंडी के पास जलभराव और तेज बहाव के कारण बड़ी मात्रा में सब्जियां पानी में बह गईं, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।कई स्थानों पर टीन शेड और अस्थायी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि तेज हवाओं ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। अचानक आई इस प्राकृतिक आफत ने शहर में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया।

पीएम सूर्य घर योजना में 1.33 लाख से ज्यादा सौर संयंत्र स्थापित : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर नागरिकों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 1 लाख 33 हजार 121 सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश में कुल 498.03 मेगावॉट सौर क्षमता विकसित की जा चुकी है। साथ ही हितग्राहियों को अब तक 942.19 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि इस योजना से परिवार ऊर्जा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना मध्यप्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और आमजन को आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में स्थापित हो रही है।

तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में उल्लेखनीय प्रगति

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी है। यहां 54 हजार 773 संयंत्र स्थापित किए गए। इससे 56 हजार 247 परिवारों को लाभ मिला है। क्षेत्र में 202.07 मेगावॉट क्षमता विकसित हुई है और 389.31 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी जारी की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में अब तक 47 हजार 734 सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे 50 हजार 323 परिवार लाभान्वित हुए हैं। कंपनी क्षेत्र में 185.09 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र स्थापित हुए हैं तथा 339.28 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी जारी की गई है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 30 हजार 614 सौर संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे 30 हजार 899 परिवार लाभान्वित हुए हैं। कंपनी क्षेत्र में 110.87 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र स्थापित हुए हैं तथा 213.60 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी वितरित की गई है।

उपभोक्ताओं को मिल रहा सीधा लाभ

योजना के तहत 1 किलोवॉट सौर संयंत्र पर 30 हजार रुपये, 2 किलोवॉट पर 60 हजार रुपये तथा 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आ रही है और वे स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रदेश सरकार और विद्युत वितरण कंपनियां योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयासरत हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिकृत वेंडरों के माध्यम से ही सौर संयंत्र स्थापित कराएं तथा सब्सिडी प्राप्ति के लिए बैंक खाते, आधार कार्ड और बिजली कनेक्शन में दर्ज नाम एक समान रखें।

लालघाटी इलाके में तीन मंजिला इमारत में आग, इसमें 6 रेस्टोरेंट

फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने एक घंटे में पाया काबू, दीवार तोड़कर अंदर घुसे दमकलकर्मी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के लालघाटी इलाके में बनी तीनमंजिला इमारत में शनिवार-रविवार की देर रात आग लग गई। इसका पता सुबह उस वक्त चला, जब पड़ोस में बनी बिल्डिंग के गार्ड ने धुआं उठता देखा।

एलर कॉम्प्लेक्स नाम की इस बिल्डिंग में 6 रेस्टोरेंट हैं। आग भोज इन रेस्टोरेंट में लगी। इमारत के बेसमेंट में बापू की कुटिया और ग्राउंड फ्लोर पर डोमिनोज का आउटलेट समेत कई छोटी दुकानें भी हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों से तीन वाटर टैंकर समेत फायर ब्रिगेड की 8 दमकलें मौके पर पहुंची। दीवार तोड़कर दमकलकर्मी अंदर घुसे। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया जा सका। गार्ड ने कहा- इमारत की खिड़की से सुबह करीब 7 बजे धुआं उठता दिखा। लगा कि ये रोज की तरह किचन से उठने वाला धुआं है। लेकिन जब लपटें दिखने लगीं तो फायर ब्रिगेड को फोन किया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका- फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने कहा- आग अनूप रिजवानी के भोज इन रेस्टोरेंट में लगी। प्राथमिक तौर पर इसका कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। यहां फायर एक्सटिंग्विशर रखे थे।पटेल ने बताया कि इस तरह के रेस्टोरेंट में अलग से किसी फायर सिस्टम की जरूरत नहीं होती है।

एलपीजी सिलेंडर समय रहते बाहर निकाले

भोज इन रेस्टोरेंट इमारत की दूसरी मंजिल पर है। इसका किचन तीसरी मंजिल पर बना है। आग किचन में लगी और नीचे की तरफ फैलती गई।आग के बीच सबसे बड़ा खतरा किचन में रखे 4 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से था, इसलिए दमकलकर्मियों ने तेजी दिखाते हुए इन्हें सबसे पहले बाहर निकाला।

प्रदेश की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पहुँची 85 हजार एमवीए के पार : ऊर्जा मंत्री तोमर

400 केवी सबस्टेशन बीना में 315 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत

भोपाल(नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी कुल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी (पारेषण क्षमता) को 85,000 एमवीए के पार पहुँचा दिया है। अब एमपी ट्रांसको की कुल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी (पारेषण क्षमता) बढ़कर 85284 एमवीए की हो गई है। इस उपलब्धि में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा 400 केवी सबस्टेशन बीना में 315 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं उसके सफल ऊर्जीकरण का योगदान रहा है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि बीना क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विकास तथा विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण सबस्टेशन की क्षमता में वृद्धि की गई है जो अब बढकर 1260 एमवीए की हो गई है।

1052 अति उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर स्थापित

एमपी ट्रांसको के पास वर्तमान में कुल 85248 एमवीए ट्रांसफार्मेशन कैपेसिटी हो गई है। कंपनी के नेटवर्क में कुल 1,052 अति उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर स्थापित हैं, जिनमें 400 केवी के 41 और 220 केवी के 220 तथा 132 केवी के 791 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा 43,079 सर्किट किलोमीटर लंबी अति उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का संचालन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कंपनी के कुल 417 सबस्टेशन कार्यरत हैं, जिनमें 400 केवी के 14 और 220 केवी के 88 तथा 132 केवी के 315 सबस्टेशन शामिल हैं।

द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला महाविद्यालय आवंटन

7 से 13 जून तक चलेगी प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई-प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी कर दी गई है। इस चरण में प्रदेशभर के 1 लाख 25 हजार 917 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीट आवंटित की गई है।

जारी सूची के अनुसार स्नातक (जी) स्तर पर 93 हजार 546 विद्यार्थियों तथा स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर 32 हजार 371 विद्यार्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं।द्वितीय चरण में महाविद्यालय आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून 2026 के बीच निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी।विभाग द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए शीघ्र प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही आवंटन संबंधी जानकारी के लिए ई-प्रवेश पोर्टल पर नियमित रूप से देखते रहें।

संपादकीय

क्या योगी सरकार पर असर होगा?

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आए दिन होने वाले पुलिस एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। यह टिप्पणी सीधे सीधे राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ है, जिसने पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर को ही अपनी पहचान बना लिया है। हालांकि कोर्ट की कड़ी टिप्पणी का योगी सरकार पर कितना असर होगा, कहना मुश्किल है। एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस के लिए संविधान नहीं, राजनीतिक आकाओं की खुशी बड़ी है। मलाईदार तैनाती के लिए उन्हें खुश करना ही उनका मकसद है। भले ही इसके लिए उन्हें किसी की अवैध गिरफ्तारी करनी पड़े या फर्जी मुठभेड़, वे करने से नहीं घबराते। उन्हें भरोसा है कि उन्हें उनके आका बचा लेंगे। यही कारण है कि यूपी में कानून का राज नहीं, बल्कि अफसरों की सनक और राजनीतिक आकाओं की खुशी करने का खेल अपने चरम पर है। इस तल्ख टिप्पणी के साथ साथ न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक ही परिवार के पिता-पुत्र और बहू के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत लंबित अपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि 35 वर्षीय गृहिणी ललिता त्यागी को एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ गिरफ्तारी को उचित ठहराने वाला कोई ठोस आधार अभिलेखों पर मौजूद नहीं था। कोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त और वर्तमान में प्रयागराज जोन के आईजी अजय कुमार मिश्रा की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं रखा और गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को स्वीकृति देने में आवश्यक सावधानी नहीं बरती। यह सच्चाई है कि पुलिस के ऐसे कथित एनकाउंटर और अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को राज्य सरकार बढ़ावा देती रही है। कुछ मामलों में यह सही भी है, लेकिन अधिकांश मामलों में तो 'जो हम करें से कायदा' वाली मानसिकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य में अफसरों की निष्पक्षता खत्म हो चुकी है और वे अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लक्षित अभियोजन चला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यूपी में एनकाउंटरों और बुलडोजर पर भी जातीय और साम्प्रदायिक राजनीति हो रही है। विपक्ष इसे जाति और धर्म के चश्मे से देख रहा है। जबकि सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बता रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 31 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक कुल 207 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इसमें 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, 17 गुर्जर-जाट, 14 एससी, 3 एसटी, 2 सिख, 8 अन्य ओबीसी और 42 अन्य जाति और धर्म के लोगों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया जा चुका है। यह आंकड़ा 2017 से 5 सितंबर 2024 तक का है। इस तरह कुल 138 हिंदू और 67 मुस्लिमों के एनकाउंटर किए गए हैं। इसी तरह सपा नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, जबकि ऊंची जाति के अपराधियों पर वैसी सख्ती नहीं होती। अखिलेश ने तो यहां तक आरोप लगाया कि यूपी में अपराध नियंत्रण अब खुद अपराधियों के हाथों में पहुंच गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भाजपा राज में महाभ्रष्ट शासन-प्रशासन ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्याओं और एनकाउंटर ने उप्र की छवि को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया है। भाजपा खुद अपराधी है।' उधर योगी सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाइयां उसकी यूएसपी हैं। जनता के बड़े वर्ग का समर्थन उसे प्राप्त है। ऐसे में कोर्ट की टिप्पणियों का उस पर कुछ भी असर होना असंभव है।

स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी से दूर भागती सरकार

नजरिया

रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी विचारक हैं।

मई के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये जिनकी विवेचना जरूरी है। सरकार ने तय किया है कि अब देश के 15 लाख सरकारी स्कूलों का संचालन एक समिति करेगी। जिसमें प्राचार्य शिक्षकों के अलावा 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों के अभिभावक याने तीन चौथाई सदस्य अभिभावक होंगे। यह भी निर्णय किया कि 30 लाख रुपये तक के जो स्कूल-भवन में सार्वजनिक कार्य होंगे वह कार्य यह समिति ही करायेगी, किसी अनुमति की ऊपर से आवश्यकता नहीं होगी। तथा अब ये शिक्षण संस्थायें सीएसआर से याने कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी के तहत सार्वजनिक या निजी उद्योगों से मदद ले सकते हैं। ऊपरी तौर पर यह निर्णय सत्ता के विकेन्द्रीकरण का लगता है और शालाओं के संचालन की कुंजी की चाबी मुख्यत अभिभावकों की समिति को देते हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि धन संबंधित चौक आदि पर प्राचार्य के साथ-साथ अभिभावक समिति के अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होंगे। निसंदेह यह निर्णय छात्रों के सबसे शुभचिंतक उनके अभिभावकों को अधिकार देते हैं। परंतु शिक्षा क्षेत्र की जो वास्तिविकतायें हैं उनके आधार पर भी सोचना होगा। क्योंकि सरकार का कार्य जमीन पर कम प्रचार पर अधिक चलता है। जैसे कुछ दिनों पहले यह कहा गया था कि नई शिक्षा नीति में प्रति छात्र बजट में 130 प्रतिशत की वृद्धि की गई, याने लगभग सवा गुना परंतु सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नई शिक्षा नीति के बाद कितने स्कूल बंद हुए और कितने छात्रों की संख्या घटी है इसका उल्लेख नहीं किया गया। जबकि तथ्य यह है कि देश में लगभग डेढ़ से दो लाख स्कूल बंद कर दिये और छात्रों की संख्या बहुत घट गई। राज्य सरकारों ने यह तर्क दिया है कि स्कूलों में छात्र नहीं थे या नगण्य थे इसलिये बंद कर दिये गये, तब इस पर भी विचार होना चाहिए कि स्कूलों में छात्र कम हुए तो इसमें किसकी जवाबदेही है। क्या यह तथ्य नहीं है कि देश के 1 लाख स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक, यहां तक की सैकड़ों हजारों स्कूलों में मात्र एक-एक शिक्षक से स्कूल चलता था और शिक्षक गाँव की जगह दूर शहर में रहते थे। इस प्रकार के हालातों के चलते लाचार होकर अभिभावकों को निजी शिक्षण, दुकानों में शरण लेनी पड़ी और जिनकी आर्थिक क्षमता अच्छी नहीं थी उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये। 2020 में नई शिक्षा नीति आने के बाद सत्ता के प्रचारकों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि शिक्षा में बहुत विकास हो रहा और अब सरकार के समक्ष शिक्षा को अंतरराष्ट्रीयकरण की चुनौती है। अब यह भी लिखा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद पहले के मुकाबले इन स्कूलों में खेलों के मैदान की सुविधा हो गई जबकि यह पूर्णतरू झूठ है। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया कि खेल मैदानों व जिम आदि की साझेदारी की व्यवस्था हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप जिन स्कूलों में खेल मैदान नहीं हैं उन्होंने दूसरे स्कूलों के साथ खेल मैदान की साझेदारी दिखा दी तथा सरकारी आंकड़ा संतुष्ट हो गया।

सच्चाई यह है कि इस शेयरिंग के नाम पर सरकार ने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं को छात्रों की उस मौलिक जरूरत से वंचित कर दिया है याने खेल कूद जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिये आवश्यक है। यही स्थिति पुस्तकालयों की है। मैं कितने ही स्कूलों को देख रहा हूँ कि बच्चों को खेलने की 1 फुट जमीन नहीं है और स्कूलों को इस शेयरिंग के नाम पर सरकार की अनुमति प्राप्त है, तथा यह मनमाना पैसा लूट रहे है। शिक्षा के अंतराष्ट्रीयकरण की चुनौती नहीं है बल्कि चुनौती शिक्षा के स्वदेशीकरण की है। भारत सरकार ने बाकायदा घोषित कर 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में आने की अनुमति दी है। पूर्व से ही विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अब सरकारी विवि और निजी विवि लगभग बराबर ही है। या हो सकता है कि निजी विवि कुछ ज्यादा हो।

आज देश में लाखों सरकारी स्कूलों के शाला भवन संख्या में अपर्याप्त है और जो हैं उनमें आवश्यक सुविधायें नहीं हैं। हजारों तो खंडहर में बदल गये। पिछले साल बरसात में मप्र के सागर जिले के शाहपुर कस्बे में एक क्षतिग्रस्त शाला भवन की दीवार गिरने से कई छात्रों की मौत हो गई और सरकार ने अपनी कार्यवाही बताने के लिये आदेश जारी कर दिया कि जो क्षतिग्रस्त शाला भवन हैं उन्हें गिरा दिया जाये। परंतु यह नहीं सोचा कि अब इन शालाओं के विद्यार्थी कहां जायेंगे। और ये शाला भवन कब बनेंगे। मप्र के सागर जिले के सानौधा गांव में मैं पिछले साल दौरे पर गया था, सानौधा गांव सागर जिले का एक बहुत बड़ा गांव है और उस गांव की शाला में आसपास के कई गांव के विद्यार्थियों जिनकी संख्या लगभग 3000 थी पढ़ते थे। वह शाला भवन तो टूट गया, नया बना नहीं, सरकार ने धन राशि दी नहीं और अब बच्चे खुले मैदान में पढ़ रहे हैं। यह तो मैंने एक घटना उद्धृत की है, न जाने इस प्रकार के कितने स्कूल मप्र व देश में होंगे। मप्र में सरकारी स्कूलों में 52 हजार शिक्षक के पद खाली हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 47 हजार शिक्षक के पद खाली हैं और 7 हजार स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है। ऐसी स्थिति अन्य राज्यों की भी है। बिहार में 2.75 लाख, झारखंड में लगभग 1 लाख, प.बंगाल में 77000, शिक्षकों के पद खाली हैं। मप्र के जिन 7 हजार स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है, उनमें 2 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं, कल्पना कीजिये कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? मजेदार बात यह है कि, 463 ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं पढ़ता है, परंतु सरकार के अनुसार इनमें 223 शिक्षक पदस्थ हैं। याने बगैर किसी पढ़ाई के शिक्षक वेतन ले रहे हैं। यह स्थिति अकेले मप्र की नहीं है बल्कि लगभग देश के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से की है।

अब यह समितियां बन जायेंगी जिनमें 75 प्रतिशत अभिभावक समिति में सदस्य होंगे परंतु जब स्कूल के भवन के लिये सरकार ने बजट ही नहीं दिया तब यह स्कूल कैसे बनेंगे? कहां से 30 लाख रुपये खर्च करेंगे, (जब पैसा ही नहीं होगा) कुल मिलाकर सरकार को एक बहाना अवश्य मिल जायेगा कि अब जवाबदार हम नहीं हैं बल्कि यह समितियां हैं। 31 मई के अखबारों में खरगोन जिले की खबर छपी है जहां अनेक स्कूलों के भवन जर्जर हैं या गिर गये हैं। नये भवन बनाने का सरकार ने जो पैसे की घोषणा की वह नहीं पहुंचा, जबकि जून माह शुरू हो रहा है याने बारिश सिर पर है, क्या ये भवन बन सकेंगे? इनमें प्रवेश लेने वाले छात्र वहाँ पढ़ेंगे? यही स्थिति शिक्षकों के बारे में होगी। क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन आदि सरकार देती है परंतु अब सरकार कहेगी कि स्कूलों में बगैर शिक्षक या शिक्षकों की कमी या अन्य कारणों से जो गिरावट होगी उसकी जवाबदारी हमारी नही है बल्कि इन समितियों की जवाबदारी है। याने अपराधी सरकार बच जायेगी तथा निर्दोष प्राचार्य व समितियों के सदस्य गुनाहगार बन जायेंगे।

नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में ड्राप आउट बहुत घट चुका है लगभग शून्य के बराबर है। क्या कभी सरकार ने इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों है? जो थोड़े भी समर्थ हैं, वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये निजी शिक्षण संस्थाओं में भेज रहे जो समर्थ नहीं हैं, वे लाचार लोग सरकारी स्कूलों में भर्ती कर तथा उनके सामने छोड़कर जाने के अलावा उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं है। अगर छोड़कर जाये तो कहां जाएं क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे न बाहर भेज सकते हैं, न निजी शिक्षण संस्थाओं में भेज सकते हैं। यही कारण है कि हाई स्कूल की शिक्षा में पहुंचते पहुंचते 55 प्रतिशत छात्र ड्राप आउट हो रहे हैं। जो शिक्षकों की शिक्षा का स्तर है उसे तो क्या कहा जाये। मप्र में नीति आयोग के अनुसार जो शिक्षकों की परीक्षायें हुई उसमें अधिकांश शिक्षक स्वत अपने विषय में 60 प्रतिशत अंक नहीं पा सके। क्या शिक्षा के इन हालात के चलते शिक्षा का कोई वास्तविक विकास हो सकेगा?

मुझे लगता है कि भारत सरकार ने विकेन्द्रीकरण के नाम पर अपना बचाव भर कर लिया है। अब प्राथमिक व स्कूली शिक्षा की हर त्रुटि की जिम्मेदारी शिक्षक-अभिभावक कमेटी की होगी। अभिभावक-शिक्षक कमेटी गांव में गाली खायेंगे और सरकार दिल्ली में बैठकर अपनी पीठ थपथपायेगी। बड़े बड़े विज्ञापन छपवायेगी। शायद ऐसे दिन आने वाले हैं कि अब शिक्षा व शिक्षक का विकास सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं के मालिकों के विज्ञापन में मिलेगा परंतु जमीन पर सूखा मैदान होगा।

गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं सभी महासागर

विश्व महासागर दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पृथ्वी पर मुख्यतः पांच प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिन्द महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। ये सभी महासागर न केवल धरती के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये सभी महासागर गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। हर साल 8 जून को 'विश्व महासागर दिवस' मनाया जाता है, जिससे मानव जीवन में समुद्रों की अहमियत, महासागरों की साफ-सफाई और उनकी सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता फैलाई जा सके लेकिन जिस रफ्तार से समुद्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे यह दिवस केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन बनकर रह गया है। 'विश्व महासागर दिवस' की वर्ष 2026 की थीम है 'पुनर्कल्पनाः हमारी जानी-पहचानी दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता', जो हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि महासागर केवल जलराशि नहीं बल्कि पृथ्वी के जीवन, जलवायु और जैव विविधता के आधार हैं।

दुनियाभर के महासागर बढ़ते मानवीय क्रियाकलापों के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार, औसतन हर मिनट एक ट्रक प्लास्टिक कचरा समुद्रों में फैंका जा रहा है। इसके अलावा, भारी मात्रा में सीवेज, औद्योगिक रसायन और जहरीले तत्व भी समुद्रों में पहुंच रहे हैं। अरबों टन प्लास्टिक कचरा हर साल महासागरों में समा जाता है, जो न तो आसानी से विघटित होता है और न ही पूरी तरह समाप्त होता है। यह वर्षों तक समुद्र में पड़ा रहकर समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी को बुरी तरह प्रभावित करता है। समुद्रों में समाते इन प्लास्टिक कणों और रासायनिक तत्वों का समुद्री वनस्पतियों और जीव-जंतुओं पर बेहद घातक असर पड़ता है। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित बहुचर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के मुताबिक, महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, जल का पीएच मान घट रहा है, पोषक तत्वों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और ऑक्सीजन की कमी भी स्पष्ट रूप से दर्ज की जा रही है। इन सभी प्रभावों का सीधा असर समुद्री पारिस्थितिकी पर पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप से भी हर वर्ष करोड़ों टन भारी धातुएं और लवणीय तत्व हिन्द महासागर में प्रवाहित हो जाते हैं। समुद्रों में सबसे ज्यादा खतरा प्लास्टिक कचरे से है, जिसे समुद्री जीव भोजन समझकर निगल जाते हैं। कई बार व्हेल, समुद्री कछुए और डॉल्फिन जैसे जीव मछली पकड़ने वाले जाल या अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट को खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि प्लास्टिक में मौजूद विषैले रसायन समुद्री जीवों के शरीर में चले जाते हैं। इन मछलियों और समुद्री जीवों को दुनिया भर में लगभग 3 अरब लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। नार्वे के पास वैज्ञानिकों को 'किलर व्हेल' के चर्बी ऊतकों में पीसीबी जैसे विषैले रसायनों के उच्च स्तर मिले हैं, जो कई देशों में दशकों पहले ही प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। साथ ही 'पीएफएएस' नामक रसायन भी इन जीवों में पाए गए हैं, जो हार्मोन संतुलन, प्रजनन क्षमता और जीवनचक्र पर बुरा असर डालते हैं। वैज्ञानिकों ने व्हेल्स के शरीर में 'ब्रॉमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स' भी खोजे हैं, जो पीढ़ियों में ट्रांसफर होकर अगली पीढ़ी तक जहरीले असर छोड़ते हैं। स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल द्वारा किए गए एक शोध में समुद्री कछुओं के पेट और मांसपेशियों में प्लास्टिक यौगिकों के उच्च स्तर पाए गए हैं। पूर्वी स्पेन के कैटलन तट पर और बेलिएरिक द्वीपों में मृत पाए गए 'लॉगरहेड' प्रजाति के 44 समुद्री कछुओं के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आए। इनके शरीर में मौजूद यौगिक हार्मोन सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल और कैंसरजनक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।

महासागरों में प्लास्टिक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया नदियां हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा नदियों के जरिए समुद्रों तक पहुंचता है। 'प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स' रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में 130 मिलियन मीट्रिक टन एकल उपयोग वाला प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ। इसमें से केवल 35 प्रतिशत को ही जलाया गया, 31 प्रतिशत को जमीन में दबाया गया और 19 प्रतिशत को खुले में या समुद्रों में फैंक दिया गया। 'साइंस एडवांसेज' जर्नल में प्रकाशित 'ओशियन क्लीनअप' संगठन के अनुसार समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली नदियों की संख्या हजारों में है लेकिन केवल एक हजार नदियां ही 80 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। इन नदियों में से अधिकांश छोटी और मध्यम आकार की ही हैं, न कि केवल विशाल नदियां, जैसा पहले माना जाता था। फिलीपींस, चीन, भारत और मलेशिया जैसी देशों की नदियां समुद्रों में प्लास्टिक पहुंचाने के मामले में अग्रणी हैं। अकेले फिलीपींस की 4800 नदियां हर साल 3.5 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक समुद्रों तक पहुंचाती हैं। भारत की 1100 से ज्यादा नदियां हर साल 1.25 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचाती हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण के अलावा जलवायु परिवर्तन भी महासागरों के लिए खतरा बन चुका है। महासागरों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण तूफानों की तीव्रता और संख्या में वृद्धि हो रही है। अरब सागर, जो पहले अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र माना जाता था, अब गर्म हो चुका है। इससे मानसून के पूर्व सत्र में लगातार पांच वर्षों तक चक्रवातों की संख्या में तेजी आई है। आईपीसीसी की जलवायु वैज्ञानिक डॉ. रोक्सी कौल के अनुसार, यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं और इससे समुद्री पारिस्थितिकी और मानव जीवन दोनों को खतरा है। बहरहाल, वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की राय में समुद्रों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक कठोर उपाय अपनाने होंगे। प्लास्टिक उत्पादन, खपत और निपटान को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीति और जन-जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी हो गया है। तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्रों को सुरक्षित और स्वच्छ बना पाएंगे।

विश्वास, रिश्ते और आत्मसम्मान

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

कहा जाता है कि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन आज के समय में यह बात धीरे-धीरे बदलती हुई दिखाई देती है। अब बहुत से रिश्ते विश्वास की गहराई पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिके हुए प्रतीत होते हैं कि हम सामने वाले की कितनी बातें मानते हैं, उसके अनुसार कितना चलते हैं और उसकी इच्छाओं के आगे कितना झुकते हैं। यदि हम उसकी हर बात को स्वीकार करते रहें, उसके विचारों से सहमत होते रहें और उसके अहंकार को चुनौती न दें, तो हम अच्छे कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने विचार रखने लगते हैं या अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, रिश्तों की परिभाषा बदलने लगती है।

जीवन में हम अनेक लोगों से जुड़ते हैं। कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं और कुछ हम स्वयं बनाते हैं। इन रिश्तों को संवारने में हम वर्षों लगा देते हैं। हम अपनी ओर से पूरी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के साथ उन्हें निभाने का प्रयास करते हैं। हम उनके सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारे कारण उन्हें कभी कोई पीड़ा न हो। हमें लगता है कि सच्चाई और समर्पण ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार जीवन हमें एक कड़वा सत्य दिखाता है।

यह सत्य यह है कि हर रिश्ता सच्चाई की कद्र नहीं करता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लिया जाता है। आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी मान लिया जाता है और आपका समर्पण एक स्वाभाविक अधिकार समझ लिया जाता है। ऐसे रिश्तों में व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता से की जाती है। वहाँ यह नहीं देखा जाता कि आपने कितने वर्षों तक साथ निभाया, बल्कि यह देखा जाता है कि आपने उनकी इच्छा के अनुसार कितना व्यवहार किया।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि चालाकी से बुने गए रिश्ते अधिक सफल दिखाई देते हैं। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलना जानते हैं, जो शब्दों का जाल बुनना जानते हैं और जो हर व्यक्ति को वही सुनाते हैं जो वह सुनना चाहता है, वे अक्सर रिश्तों में विजेता दिखाई देते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति सच्चा होता है, स्पष्ट होता है और मन में कुछ तथा मुख पर कुछ और नहीं रखता, उसे कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उसकी सच्चाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक वह अपने आत्मसम्मान से समझौता न कर ले।

लेकिन यहीं सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान का त्याग कर देना चाहिए? क्या किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए स्वयं को खो देना उचित है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपना सम्मान खो देता है, उस दिन वह केवल दूसरों की अपेक्षाओं का पात्र बनकर रह जाता है। उसका अपना अस्तित्व धुंधला पड़ने लगता है।

यह सत्य है कि आत्मसम्मान के साथ जीने का मार्ग आसान नहीं होता। कई बार आपको गलत समझा जाएगा, कई बार आपकी नीयत पर प्रश्न उठाए जाएँगे और कई बार वे लोग भी दूर चले जाएँगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। उस समय मन टूटता है, निराशा घेरती है और यह महसूस होता है कि शायद सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वास्तव में सच्चाई का मूल्य तत्काल नहीं मिलता। वह धीरे-धीरे अपना फल देती है।

सच्चाई एक बीज की तरह होती है। जब उसे बोया जाता है, तब वह मिट्टी के भीतर छिपा रहता है। लोग उसे देखकर हँस भी सकते हैं कि यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन समय आने पर वही बीज वृक्ष बनता है, छाया देता है और फल भी देता है। ठीक उसी प्रकार आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा और आपका सच्चा चरित्र भी एक दिन आपके जीवन को संवारता है। हो सकता है कि आज लोग आपकी कद्र न करें, लेकिन आने वाला कल आपके धैर्य और सत्यनिष्ठा का सम्मान अवश्य करेगा।

इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपकी सच्चाई हार रही है और चालाकी जीत रही है, तो निराश मत होइए। जीवन का प्रत्येक परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ जीतें समय के साथ सामने आती हैं। अपने भीतर की अच्छाई को मत छोड़िए, अपनी सच्चाई को मत त्यागिए और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत बेचिए। संसार की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को खो देना सबसे बड़ी हार है।

अंततः जीवन हमें यही सिखाता है कि विश्वास सबसे पहले स्वयं पर होना चाहिए। यदि कोई विश्वास स्थायी है, तो वह आपका अपने चरित्र पर विश्वास है और ईश्वर पर विश्वास है। मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन आपका सत्य और ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। इसलिए लोगों से प्रेम कीजिए, रिश्तों को निभाइए, लेकिन अपनी आस्था का केंद्र केवल दूसरों को मत बनाइए। स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहिए। यही विश्वास अंततः आपके जीवन को सही दिशा देगा और आपके आने वाले कल को उज्ज्वल बनाएगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कौड़ी बोले झइयम-झइयम-झा

व्यंग्य

जवाहर चौधरी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

कौड़ी अब मुहावरों में रह गई है किन्तु कुछ लोग अपनी प्रतिभा से कौड़ी बाजार के हो जाते हैं। माना जाता है कि जो दिन भर झूठ बोले, चाटुकारिता करे, दलाल न हो पर दलाली करे वह फूटी कौड़ी का। पहले भी यही रेट था यही रेट आज भी है। कौड़ी ऐसी मुद्रा है जो किसी दूसरी मुद्रा के मुकाबले उठती गिरती नहीं है। कौड़ी औकात के बाजार में चलने वाली अकेली होती है। कौड़ी का अपना पैमाना है । किसी को पचास लाख रुपए महीना मिल रहा हो तब भी वह दो कौड़ी का हो सकता है। कोई बहुत सुन्दर हो तब भी दो कौड़ी का हो सकता है। कोई पॉवर फुल हो तब भी इतिहास में उसे 'दो कौड़ी का' कह कर दर्ज किया जाता है। कोई झूठा, बेईमान, ढोंगी, समाज में वैमनस्य फैलाने वाला हो उसे फिक्स रेट फूटी कौड़ी वाला आईपीओ (IPO) माना जा सकता है। मशहूर माइकल जैक्सन बाल यौन शोषण के आरोप के बाद दो कौड़ी के माने गए । कौड़ी चरित्र पर प्राइज टैग है। इस समय जो 'नोबल शांति' युद्ध चल रहा है उसमें कुछ कौड़ियाँ नजर आती हैं । इसमें आमतौर पर दो ही रेट होते हैं, फूटी कौड़ी या फिर दो कौड़ी। फूटी कौड़ी प्रायः चलन में कम होती है। कौड़ी क्रम में सबसे नीचे फूटी कौड़ी होती है। फूटी कौड़ी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। फूटी दूसरों को कुछ भी बोल सकती है। इतिहास में झाँक कर देखो तो पता चलता है कि वर्षों पहले तमाम लोग जो दो कौड़ी के थे वे आज भी उतने के ही माने जा रहे हैं! संविधान के हस्तक्षेप के बावजूद वे तीन कौड़ी के भी नहीं

कौड़ी का अपना पैमाना है । किसी को पचास लाख रुपए महीना मिल रहा हो तब भी वह दो कौड़ी का हो सकता है। कोई बहुत सुन्दर हो तब भी दो कौड़ी का हो सकता है।

हो पाए। उनके हितैषी आगे आए और वोटों का कारोबार करने लगे लेकिन इनके भाव नहीं बदले। खरीदने वाले कौड़ियों के मोल में इनकी सहमति खरीदते आ रहे हैं। कौड़ी बाजार में महंगाई नहीं होती है, इसलिए किसी राजनीतिक दल ने कौड़ी को मुद्दा नहीं बनाया है। इधर भक्त-भीड़ पुराने वैभव की ओर लौटने के लिए झइयम-झइयम-झा कर रहे हैं । उन्हें लगता है नया भले ही सोने का हो पर उसमें 'वो वाला' वैभव नहीं है। पुराने समय में कौड़ियों से खरीददारी की जा सकती थी। स्त्रियां गले में कौड़ी की माला पहनती थी और हाथ, कान, कमर में भी कौड़ी के ज़ेवर। तो वैभव की श्रेणी में रखना ही पड़ेगा। सोना चाँदी बंद है, सबको पुराने वैभव की ओर लौटना है । जो लोग लौटाना नहीं चाहेंगे उन्हें कली सूची में डाला जा सकता है । नये ज्ञान को हटा कर पुराने के लिए जगह बनाई जाना जरूरी है । हर पुरानी चीज कीमती थी, आज और ज्यादा कीमती है । हालाँकि कुछ उराने-पुराने फैंक देने योग्य भी हैं, जैसे पुराने बूढ़े नेता या घर में पड़े अपने माँ-बाप या इतिहास की किताबें, या फिर इतिहास खुद। गंगा जमुना में 'वो वाला' वैभव है, भले ही लैब रिपोर्ट कह रही है कि गंदगी है। कहीं खोदाई में वैभव निकल रहा है तो कहीं कथाओं में से निकल कर लाउडस्पीकर पर चीख रहा है । असल में वैभव है या नहीं इस पर अनेक टीवी डिबेटें हो सकती हैं । टीवी वाले जानते हैं कि जनता को मूर्ख कैसे बनाए रखा जा सकता है। और टीवी वालों से कैसे काम लिया जाए यह सरकार अच्छी तरह जानती है। पता ही नहीं पड़ता कि टीवी कब सरकार होता है और सरकार कब टीवी ! एंकर अगर आँखें दिखाते खऊवाने दौड़े तो पेनलिस्ट सहम जाते हैं। यह डिबेट का वैभव है। दिनरात टीवी चल रहा है, झूठ नृत्य कर रहा है । एंकर देव कौड़ी वर्षा कर रहे हैं । राजनीतिक किन्नर आशीर्वाद दे रहे हैं। जय जगत, लगे रहो भगत ।

न्याय और कानून

निष्पक्ष चुनाव

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

एसआईआर चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार

'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (एसआईआर) के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि वे मूल रूप से मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होती हैं। यह प्रक्रिया नागरिकता का निर्धारण करने वाली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसा कि निर्वासन या नागरिकता कानूनों के तहत समझा जाता है। बल्कि, यह एक चुनावी सत्यापन प्रक्रिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूचियों में केवल पात्र नागरिक ही शामिल रहें।

सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में अपने ताजा फैसले में भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) की वैधता को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि गहन पुनरीक्षण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एसआईआर करने की शक्ति है। इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधिपति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन रिट याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जिनमें पिछले साल जून में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने के लिए जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया का लक्ष्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था और इन दोनों के बीच सीधा संबंध था।

मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि जब कानून खुद ही किसी भी समय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर और चुनाव आयोग को उचित लगने वाले तरीके से, विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है, तो इस विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं के हर पहलू के अनुरूप नहीं है। हमारी सुविचारित राय में यह विवादित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके नियमों की जगह नहीं लेता है। यह धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक जनादेश में नई जान डालता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से बाहर जाकर काम किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि वे मूल रूप से मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण, जिनमें पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद से चार दशकों से अधिक का समय बीत जाना, पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर नामों का जोड़ा जाना और हटाया जाना, तथा तेजी से हुए शहरीकरण और प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में नामों के दोहराव और अशुद्धियों की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए गहन पुनरीक्षण आवश्यक है। प्रक्रिया ने कानून का उल्लंघन नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज किया कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950' और 'मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960' के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को भी खारिज किया कि इस प्रक्रिया ने उन लोगों की नागरिकता की धारणा को खत्म कर दिया, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की भी विवेचना की थी कि क्या भारतीय चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने की शक्तियां हैं। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। यह बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है। यह उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि जैसे कई अन्य राज्यों में अभी भी जारी है।

इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस कानूनी सवाल का फैसला करेगा कि क्या भारतीय चुनाव आयोग के पास इस अभ्यास को करने की शक्ति है। इस साल 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ज्यादातर याचिकाएं पिछले साल जून में दायर की गयी थी, जब भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का फैसला किया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव तथा विभिन्न पार्टियों के कुछ सांसदों महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी. वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले आदि ने ये याचिकाएं प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण नागरिकता सत्यापन का एक चोर-दरवाजा वाला अभ्यास याचिकाकर्ताओं ने व्यापक संवैधानिक चुनौती पेश करते हुए यह तर्क दिया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सूची के संशोधन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे को मौलिक रूप से बदल देता है।

उनका मुख्य तर्क यह था कि यह अभ्यास चुनाव आयोग को असल में नागरिकता का फैसला करने वाली संस्था में बदल देता है। उनके अनुसार, चुनावी पंजीकरण कानून

आयोग को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वह उन नागरिकों से, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज हैं, यह मांग करे कि वे दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से अपनी नागरिकता को नए सिरे से साबित करें। उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकता से जुड़े सवालों का समाधान केवल नागरिकता अधिनियम और संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित कानूनी तंत्रों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, न कि किसी चुनावी गणना प्रक्रिया के जरिए। याचिकाकर्ताओं ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन जैसा अभ्यास करार दिया। उनकी ओर से भी यह तर्क दिया गया कि यह अयोग्यता की एक धारणा पैदा करता है। यह मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ डाल देता है। यह प्रक्रिया स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। इससे जुड़ी एक और चिंता यह उठाई गई कि इस प्रक्रिया से 'लंबित नागरिकता' की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि किसी व्यक्ति का नाम सत्यापन होने तक मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नागरिकता का औपचारिक निर्धारण किए बिना ही, प्रभावी रूप से एक बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गणना प्रपत्रों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या संबंधित चुनावी नियमों के तहत कोई स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहीं है। इससे यह प्रक्रिया कानूनी रूप से कमजोर हो जाती है। चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' की धारा 21(3) कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ व्यापक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं देती है। यह प्रावधान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए विशेष पुनरीक्षण की अनुमति देता है। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य किसी बड़े, राष्ट्रव्यापी अभियान के बजाय लक्षित और विशेष हस्तक्षेप करना है।

यह भी तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण को उचित ठहराने वाले निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट या राज्य-विशिष्ट कारणों को बताने में विफल रहा है। इससे मनमानी की आशंका पैदा होती हैं।

याचिकाकर्ताओं ने लाल बाबू हुसैन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया। इस फैसले में कहा गया है कि एक बार किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाने के बाद उसकी नागरिकता के पक्ष में एक धारणा बन जाती है। इसके विपरीत साबित करने का बोझ आपत्ति उठाने वाले व्यक्ति पर होता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण इस सिद्धांत को उलट देता है। क्योंकि, यह पहले से ही पंजीकृत मतदाताओं को अपनी पात्रता फिर से साबित करने के लिए बाध्य करता है। भारतीय चुनाव आयोग, चुनावी शुद्धिकरण, न कि नागरिकता का निर्धारण।

इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रकृति को मौलिक रूप से गलत समझा है। आयोग का मुख्य तर्क यह था कि यह प्रक्रिया नागरिकता का निर्धारण करने वाली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसा कि निर्वासन या नागरिकता कानूनों के तहत समझा जाता है। बल्कि, यह एक चुनावी सत्यापन प्रक्रिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूचियों में केवल पात्र नागरिक ही शामिल रहें।

आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान नागरिक-आधारित मताधिकार की परिकल्पना करता है। इसलिए गैर-नागरिकों को मतदाता सूचियों से बाहर करके चुनावी शुद्धता बनाए रखना उसका संवैधानिक दायित्व है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन जैसी प्रक्रिया के साथ की गई तुलना खारिज करते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किसी जबरदस्ती वाली जांच के बजाय एक ऐसे सत्यापन मॉडल को अपनाता है, जिसे उसने उदार और नरम-दृष्टिकोण वाला मॉडल बताया है। लाल बाबू हुसैन मामले पर याचिकाकर्ताओं के भरोसे के संबंध में आयोग ने तर्क दिया कि वह पूर्व-निर्णय तथ्यों के आधार पर इस मामले से अलग है। आयोग ने कहा कि उस पिछले मामले में परिस्थितियां काफी भिन्न थीं, जिनमें सत्यापन प्रक्रिया में पुलिस की संलिप्तता और प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का अभाव शामिल था।

इसके विपरीत, मौजूदा मामले में आयोग ने यह तर्क दिया कि यह प्रक्रिया चुनाव अधिकारियों द्वारा संचालित की जा रही है, न कि पुलिस अधिकारियों द्वारा। साथ ही इसमें पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं। आयोग ने यह भी तर्क दिया कि मतदाता सूचियों में पहले से शामिल होने का साक्ष्य के तौर पर महत्व बना हुआ है और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने वैधानिक योजना के तहत अपने अधिकार का और बचाव करते हुए तर्क दिया कि मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन की शक्ति में चुनावी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जहां भी आवश्यक हो, गहन सत्यापन करना भी अनिवार्य रूप से शामिल है। आयोग ने राजनीतिक मंशा के आरोपों को भी यह कहते हुए खारिज किया कि उसकी भूमिका संस्थागत और संवैधानिक है, न कि इस प्रक्रिया से जुड़ी राजनीतिक बातों के प्रति प्रतिक्रियात्मक।

मीडिया

राजीव खंडेलवाल

लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास

टीआरपी का मायाजाल, दर्शक भी उतने ही गुनहगार!

मीडिया की ''आन बान शान'' के आकलन का एकमात्र बैरोमीटर ''टीआरपी'' है। टीआरपी मतलब (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) किसी टीवी कार्यक्रम या चैनल की लोकप्रियता का इकलौता मापदंड है। यह बताता है कि ''लक्षित'' दर्शकों में से कितने प्रतिशत लोग किसी विशेष कार्यक्रम या चैनल को देख रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो, टीआरपी मीडिया जगत की वह ''मुद्रा'' (करेंसी) है, जिससे उसका बाजार भाव व रुतबा तय होता है। दूसरे शब्दों में यह व्यापारी के लिए व्यापार की बिक्री के आंकड़े के महत्व के समान है।

आज के दौर में मीडिया की शक्ति निर्विवाद है। सरकारों की छवि निर्माण से लेकर जनमत को प्रभावित करने तक उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के उभार से लेकर अन्ना आंदोलन और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उदय तक मीडिया की भूमिका निसंदेह महत्वपूर्ण रही है। शायद इसीलिए मीडिया से सामान्यतया कोई ''पंगा'' तब तक नहीं लेना चाहता है, जब तक पानी सिर के ऊपर न निकल जाए।

फिल्मी कलाकार ''सुशांत सिंह राजपूत'' का मीडिया ट्रायल हो या ''ऑपरेशन सिंदूर'' जैसी संवेदनशील सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों की अतिरंजित कवरेज जैसे अनेकानेक विषय; पर मीडिया का प्रसारण हर बार एक शब्द गूंजता है ''टीआरपी।''

टीआरपी क्या है: मीडिया की ''आन बान शान'' के आकलन का एकमात्र बैरोमीटर ''टीआरपी'' है। टीआरपी मतलब (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) किसी टीवी कार्यक्रम या चैनल की लोकप्रियता का इकलौता मापदंड है। यह बताता है कि ''लक्षित'' दर्शकों में से कितने प्रतिशत लोग किसी विशेष कार्यक्रम या चैनल को देख रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो, टीआरपी मीडिया जगत की वह ''मुद्रा'' (करेंसी) है, जिससे उसका बाजार भाव व रुतबा तय होता है। दूसरे शब्दों में यह व्यापारी के लिए व्यापार की बिक्री के आंकड़े के महत्व के समान है।

टीआरपी का महत्व: किसी चैनल की टीआरपी जितनी अधिक होती है, विज्ञापनदाताओं से उसे महंगे दर पर अधिक विज्ञापन मिलने से उतनी ही अधिक आय प्राप्त होती है। यही कारण है कि चैनलों के बीच दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की निरंतर गला-काट प्रतिस्पर्धा होकर यह कई बार निम्न स्तर तक चली जाती है।

टीआरपी केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है। अधिक दर्शक संख्या चैनल की राजनीतिक दखलंदाजी और सामाजिक प्रभावशीलता भी बढ़ाती है। सत्ता, कॉरपोरेट जगत और रसूखदार तबके स्वाभाविक रूप से उन मंचों के निकट रहना चाहते हैं, जिनकी पहुंच जनता के बीच व्यापक हो। मीडिया हाउस को भी सत्ता और कॉरपोरेट जगत के निकट आने का फायदा मिलता है। इसलिए वे उसके आस-पास रहने का प्रयास करते है।

टीआरपी की गणना: भारत में टीआरपी की गणना और प्रकाशन BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) द्वारा किया जाता है। यह ब्रॉडकास्ट एडवरटाइजर्स और एजेंसियों का संयुक्त संगठन है। इसके लिए देशभर के चयनित घरों में विशेष उपकरण (people meter) लगाए जाते हैं, जो यह रिकॉर्ड करते हैं कि कौन-सा चैनल कितनी देर तक देखा गया।

इस आंकड़े का विश्लेषण आयु, लिंग, ग्रामीण-शहरी पृष्ठभूमि तथा सामाजिक-आर्थिक वर्गों के आधार पर ''वेटेज'' देकर किया जाता है और फिर पूरे देश के दर्शकों का अनुमान लगाया जाता है। इसी आधार पर साप्ताहिक टीआरपी भी रिपोर्ट जारी होती है।

दोषी कौन: जब भी कोई चैनल किसी घटना को ''राई का पहाड़'' बनाकर सनसनीखेज तरीके से प्रसारित करता है (कुछ उदाहरण ऊपर दिए गए हैं), तो तुरंत तोहमत

लगती है कि यह सब ''टीआरपी का खेल'' है। मानो पत्रकारिता की सारी विकृति की जड़ यही एक शब्द है। तथापि यह आरोप पूरी तरह निराधार नहीं है। लेकिन क्या सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ना आधे सच को देखना नहीं? वास्तव में इसी आरोप में जनता की अंशदायी (योगदान), ''सहभागिता'' भी छुपी हुई है। टीआरपी किसी चैनल के कार्यक्रम में नहीं, बल्कि वह दर्शकों के ड्राइंग रूम में बनती है।

टीआरपी आती कहां से है: यदि दर्शक किसी कार्यक्रम को देखना ही बंद कर दें, तो उसकी टीआरपी स्वतः गिर जाएगी। बाजार का सिद्धांत है ''जो बिकता है, वही बाजार में दिखाई देता है।'' यदि सनसनी, विवाद, भावनात्मक उत्तेजना और उत्तेजक बहसों वाले कार्यक्रम लगातार ऊंची टीआरपी प्राप्त करते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि दर्शकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें देख भी रहा है। ऐसे में मीडिया की आलोचना विडंबना देखिये, जिस कंटेंट को लोग ''चटकारे लेकर'' देखते हैं, भरी महफिल में उसको कोसते भी है। मीडिया को कोसना और खुद को ''दूध का धुला'' बताना अपना ''उल्लू सीधा करना'' होगा। यहीं से मुद्दे का दूसरा पक्ष सामने आता है।

करते समय दर्शकों की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना वास्तविकता से आंख मूंदना होगा। क्या इसके लिए जनता भी दोषी नहीं है? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मिठाई खरीद कर खाए और फिर केवल हलवाई को मधुमेह के लिए दोषी ठहरा दे।

मीडिया कम जिम्मेदार नहीं: इसका अर्थ यह नहीं कि मीडिया अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाता है। पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं, ''धर्म'' भी है। इसका उद्देश्य केवल दर्शकों की पसंद का पीछा करना नही, बल्कि समाज को तथ्यपरक, संतुलित और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने का सार्वजनिक दायित्व भी है। दर्शकों की कमजोरी को ''कैश'' करने लगे तो प्रेस का मूल उद्देश्य ही धराशायी हो जाएगा। लोकतंत्र में मीडिया समाज का दर्पण है, तमाशा नहीं।

टीआरपी की अंधी दौड़ के चलते यदि समाचार, मनोरंजन और फूहड़ मजाक, व्यंग की रेखा धुंधली हो जाए, तथ्यों की जगह उत्तेजना ले ले और ''बहस'' की जगह ''शोर'' हावी हो जाए, एक कार्यक्रम का नाम ही ''हल्ला बोल'' ही है, दंगल, महाभारत, आर-पार है तो पत्रकारिता की साख ''मिट्टी में मिलना'' तय है।

शायद यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में दर्शक पारंपरिक टीवी मीडिया से हटकर डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हुए हैं। सूचना के स्रोत बढ़े हैं और दर्शकों के पास विकल्प भी।

टीवी दर्शकों के गिरते आंकड़े: हाल में ही अंजना ओम कश्यप ने ''हल्ला बोल'' कार्यक्रम में प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट के मालिकों के संबंध में कोचिंग माफिया के संबोधन के साथ बहुत ही विवादित टिप्पणी की थी, जो ''आग की तरह'' वायरल हुई। इसका कारण भी टीआरपी बताया गया। लेकिन शायद यह पहली बार हुआ कि मीडिया के ''हल्ला बोल'' का जवाब सोशल मीडिया ने भी हल्ला बोल कर दिया। टीवी चैनल्स खासकर मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसे एक वर्ग ने गोदी मीडिया का नाम दिया, को संभल जाना चाहिए कि उनकी टीआरपी पिछले कुछ सालों में गिरकर कहां पहुंच गई है? लगभग 30 से 40 मिलियन दशकों की कमी पिछले 10 सालों में आई है और अगले 10 सालों में यह कमी 70 मिलियन तक पहुंचाने की आशंका है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग पलायन कर सोशल मीडिया, डिजीटल प्लेटफॉर्म की ओर चला गया है (लगभग चार गुना)। रेवेन्यू में 10 गुना वृद्धि हुई जो 2024 में टीवी रेवेन्यू को पार कर गई। विज्ञापन की कुल आय में लगभग 60 की भागीदारी सोशल मीडिया की हो गई। शायद इसीलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स के मामले में रैंकिंग मापने वाली संस्था ऋस्स के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में खिसककर 157 वें स्थान पर आ गया।

टीआरपी के खेल में दोष व दायित्व दोनों साझा हैं। मीडिया वही परोसता है, जिसे देखने वाले मौजूद हैं, (मांग और पूर्ति का सिद्धांत) और दर्शक वही देखते हैं, जो उन्हें लुभाता है।

स्वस्थ पत्रकारिता और स्वस्थ जनमत दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती।

सामयिक

भूपेन्द्र गुप्ता

लेखक कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष हैं।

क्या भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के साथ न्याय हुआ है?

भारतीय राजनीति में शायद ही कोई नेता ऐसा रहा हो जिसकी आलोचना और चर्चा उतनी हुई हो जितनी राहुल गांधी की। पिछले डेढ़ दशक में उन्हें कभी 'अनुभवहीन', कभी 'अनिच्छुक राजनेता' और कभी 'वंशवाद का प्रतीक' बताया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी राहुल गांधी को "well-intentioned dilettante" कहा था–अर्थात अच्छी नीयत रखने वाला किंतु शौकिया राजनेता। प्रश्न यह है कि क्या यह मूल्यांकन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या समय ने इस निष्कर्ष को चुनौती दी है?

राहुल गांधी के आलोचक प्रायः उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को उनके राजनीतिक जीवन का केंद्रीय तथ्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से आते हैं। किंतु क्या किसी नेता का अंतिम मूल्यांकन उसके उपनाम से होना चाहिए या उसके सार्वजनिक जीवन के कार्यों से?

यदि केवल वंशवाद ही कसौटी है, तो भारतीय राजनीति के अनेक दलों और नेताओं की वैधता पर समान प्रश्न उठने चाहिए। लगभग हर बड़े दल में ऐसे नेता मौजूद हैं जिनकी प्रारंभिक राजनीतिक पहचान पारिवारिक विरासत से बनी। किंतु उनके मूल्यांकन में अक्सर उनकी राजनीतिक क्षमता, जनाधार और चुनावी प्रदर्शन को भी महत्व दिया जाता है। राहुल गांधी के मामले में यह उदारता कम दिखाई देती है।

पिछले वर्षों में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में एक अलग प्रकार की राजनीतिक शैली प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' केवल राजनीतिक अभियान नहीं थे; वे जनता से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के प्रयास भी थे। हजारों किलोमीटर की यात्राएँ, लगातार जनसंपर्क और विभिन्न सामाजिक समूहों से संवाद किसी ऐसे नेता की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसे राजनीति में रुचि नहीं है, यह कहना कठिन हो जाता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि राहुल गांधी ने अत्यंत प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक नेता रहे हैं जो एक बड़ी चुनावी हार के बाद सार्वजनिक जीवन के हाशिये पर चले गए। इसके विपरीत राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विपक्षी चेहरों में बने रहे, लोकसभा में चुने जाते रहे और विपक्षी विमर्श को प्रभावित करते रहे। किसी भी लोकतंत्र में यह स्वयं एक राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। यहीं रामचंद्र गुहा जैसे विश्लेषकों के मूल्यांकन पर प्रश्न उठता है। यदि किसी नेता की सफलता का मापदंड केवल सत्ता प्राप्ति है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का महत्व कम हो जाता है। और यदि सफलता का मापदंड जनसंपर्क, वैचारिक हस्तक्षेप, संगठनात्मक प्रभाव और सार्वजनिक स्वीकार्यता भी है, तो राहुल गांधी का मूल्यांकन अधिक संतुलित होना चाहिए।

गुहा की आलोचना का एक दूसरा पक्ष भी है। वे कांग्रेस में गांधी परिवार की केंद्रीय भूमिका को भारतीय लोकतंत्र की समस्या मानते हैं। यह एक वैध तर्क है। किंतु निष्पक्ष विश्लेषण की मांग यह है कि वही कसौटी अन्य दलों और अन्य राजनीतिक परिवारों पर भी समान कठोरता से लागू की जाए। यदि किसी दल में वंशानुगत नेताओं की उपस्थिति राजनीतिक क्षमता का प्रमाण मानी जाती है, तो दूसरे दल में वही तथ्य लोकतांत्रिक दोष का पर्याय कैसे बन जाता है?

राहुल गांधी का मूल्यांकन करते समय यह स्वीकार करना आवश्यक है कि उनकी राजनीति से असहमति संभव है। उनकी रणनीतियों की आलोचना भी की जा सकती है। किंतु उन्हें केवल एक राजनीतिक उपनाम तक सीमित कर देना उनके सार्वजनिक जीवन के वास्तविक प्रयासों की उपेक्षा होगी।

लोकतंत्र में किसी नेता का अंतिम मूल्यांकन इतिहास करता है, और इतिहास केवल वंश नहीं देखता; वह यह भी देखता है कि कठिन समय में किसने संघर्ष किया, जनता से संवाद किया और अपने विचारों के लिए कितना जोखिम उठाया। राहुल गांधी के समर्थक इसी आधार पर कहते हैं कि उनके बारे में प्रचलित धारणाओं और उनके वास्तविक राजनीतिक प्रयासों के बीच की दूरी को अब नए सिरे से परखा जाना चाहिए।

इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि राहुल गांधी कौन हैं; प्रश्न यह भी है कि क्या भारतीय सार्वजनिक विमर्श उन्हें उसी कसौटी पर परखता है जिस पर वह अन्य नेताओं को परखता है। यदि उत्तर 'नहीं' है, तो शायद पुनर्मूल्यांकन का समय आ चुका है।

रामचंद्र गुहा से इतना.तो आग्रह किया ही जाना चाहिए कि जिन राजनीतिक दलों ने वंशवादी प्रतिष्ठा के आधार पर ही दूसरे दलों से नेताओं को तोड़ा और अपने दल में शामिल किया उन पर वे क्या राय रखते हैं।क्या सिंधिया,रीता बहुगुणा,वीरेन्द्र सिंह,चौटाला,वरुण गांधी ,अमरेंद्र सिह ,पटवा,सखलेचा,राजवीर सिंह,पंकज सिंह,पीयूष गोयल,बांसुरी स्वराज,अनुराग ठाकुर ,अशोक चव्हाण, देवड़ा,प्रवेश वर्मा आदि भी समीक्षा के समानाधार पर कसे जाते हैं? इन सबकी योग्यता इनका परिवार ही है.लेकिन राहुल गांधी ही बौद्धिक पूर्वाग्रहों का आसान शिकार हैं क्यों?

वंश किसी नेता को अवसर तो दे सकता है, लेकिन जनता बार-बार केवल वंश के आधार पर वोट नहीं देती। लोकतंत्र में विरासत प्रवेश-द्वार हो सकती है, स्थायित्व नहीं। राहुल गांधी की आलोचना कीजिए, उनकी राजनीति से असहमत रहिए, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन के दो दशकों के संघर्ष, यात्राओं और जनसंवाद को केवल एक उपनाम में समेट देना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। तब तो और भी नहीं जब न्यायाधीश इतिहासकार के रूप में जाना जाता हो।

भारतीय खेल प्राधिकरण, धार द्वारा आयोजित 'विश्व साइकिल दिवस'

संडे ऑन साइकिल' में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने शिरकत की

धार। भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलों इंडिया योजना मिशन पहल के तहत भारत के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और फिटनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की कड़ी में इस रविवार को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम तथा फिटनेस रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रुप में केन्द्रीय राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर तथा विशेष अतिथि के रुप में कलेक्टर राजीव रंजन मीना एवं एसपी सचिन शर्मा सम्मिलित हुए।

श्रीमती सावित्री ठाकुर ने धारवासियों को पर्यावरण संरक्षण एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढाने हेतु सायकल का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया। साईकिल रैली में धार जिले के विंग्स पोद्दार लर्न विद्यालय,जिला पुलिस बल के महिला एवं पुरूष आरक्षक,खेल एवं युवा कल्याण विभाग, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, सेंट जार्ज स्कूल के बच्चो एवं धार जिले के विभिन्न विद्यालयों से आये बच्चों एवं जनसमान्य के द्वारा साई सेंटर में सम्मिलित होकर फिटनेस को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्धेश्य से भागीदारी की गई । कार्यक्रम में आये प्रतिभागियो को स्ट्रेचिंग, रस्सी कूद एवं जुम्बा जैसी गतिविधियों में भी सक्रियता से उत्साहपूर्वक भाग लिया गया।

डीएम राजीव रंजन मीना एवं एसपी सचिन शर्मा द्वारा सायकल रेली में भाग लिया गया एवं सभी प्रतिभागियों को साइकिल चलाने को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विंग्स पोद्दार विद्यालय के डायरेक्टर आशीष महंत, राजेंद्र कुमार साहू (प्रिंसिपल) एवं प्रकाश पटेल (खेल प्रशिक्षक) की भागीदारी रही। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन की गरिमा वर्मा एवं पूनम मिश्रा के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जानकारी दी।

भारतीय खेल प्राधिकरण, धार द्वारा प्रतिभागियो को टी-शर्ट तथा दीर्घा राजावत (युवा अधिकारी, माय भारत) के द्वारा कैप का वितरण किया गया। NORTIC HEALTH CARE PVT LTD के मोनू रजक तथा प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा एनर्जी ड्रिंक का वितरण किया गया। फिटनेस साइकिल रैली एसटीसी धार से त्रिमूर्ति चौराहा से वापस भारतीय खेल प्राधिकरण तक लगभग 4 किलोमीटर के साथ समाप्त हुई।

भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से केंद्र प्रभारी नरेश कुमार भावसार, ताईक्वांडो प्रशिक्षक ओमप्रकाश माखनिया, प्रशिक्षक तीरंदाजी राजेश तम्बोलिया, सहायक प्रशिक्षक तीरंदाजी विकास कुमार, मनीष लोधी एवं अन्य स्टाफ कर्मचारीगण और साई के खिलाड़ी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास में अनोखे खेल का आरोप ,आवास बेचकर फिर अतिक्रमणःपार्षद बैलबंशी

सोहागपुर। नगर पंचायत परिषद में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलवशी हमेशा नगर पंचायत परिषद की गलतियों को सोशल मीडिया पर डालकर हमेशा उजागर करते रहते हैं। नगर की 15 सदस्यीय परिषद में एक दुक्का पार्षद ही जनता-जनार्दन की समस्यायों को उठाते रहते हैं। इसी तारतम्य में श्री बैलवशी ने एसडीएम एवं नगरपालिका अधिकारी को इंगित करते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि नगर में एक अनोखा खेल चल रहा है। जिसमें कुछ लोगों ने शासकीय भूमि पर पहले कभी अपना बसेरा बनाया । तथा शासन ने उन्हें पट्टे भी दे दिए । ऐसे नागरिकों को प्रधान मंत्री आवास की राशि भी दे दी। बड़े मजे की बात तो यह है कि इसमें से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बेचकर फिर दूसरी जगह शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके टपरिया बना कर रहने लगे। कुछ लोगों ने प्रधान मंत्री आवास में एक सदस्य को रहने दिया । बाकी अन्य सदस्य ने दूसरी जगह शासकीय भूमि पर टपरिया डाल ली है। पार्षद धर्मदास बैलबंशी ने शासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगो की जांच की जाए । तथा उनका अतिक्रमण हटाने का कष्ट करें। वहीं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बेच दिए हैं । ऐसे मामलों में बेचने वाले एवं खरीदने वाले (विक्रेता और क्रेता) पर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाकर उचित कार्यवाही करें । इसके साथ प्रधानमंत्री आवास की राशि वसूली भी की जाए। ताकि फिर कोई शासन से ऐसी धोखाधड़ी न कर सके।

रामगंज वार्ड में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान, किया जुर्माना , चेतावनी दी

सोहागपुर। नगर पंचायत परिषद एवं राजस्व विभाग के संयुक्त अभियान में नगर को सुव्यवस्थित एवं अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से आज रामगंज वार्ड में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सार्वजनिक मार्गों, शासकीय भूमि एवं आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों का निरीक्षण करके कार्रवाई की गई। इसी अवसर पर अतिक्रमणकारियों के सामान एंट्री को लेकर बार बार मिन्नतें की गई कि आप हमें एक मौक़ा दे।इसी मोके पर तीन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कुल 12, हजार 5सौ रूपये का

जुर्माना लगाया गया। तथा उक्त राशि की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर रखी गई कबाड़ सामग्री को जप्त भी किया गया। अधिकारियों द्वारा संबंधित अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वे अपना शेष अतिक्रमण स्वयं हटाकर सार्वजनिक स्थलों को खाली करें,अन्यथा नगर पंचायत परिषद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी तथा उससे होने वाले व्यय एवं दंड की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्तियों की होगी।

अभियान के अवसर पर अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों को भी समझाइश दी कि सड़क, नाली, फुटपाथ एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किया गया अतिक्रमण न केवल यातायात एवं आमजन की सुविधा में बाधा उत्पन्न करता है।बल्कि नगर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए सभी नागरिक निर्धारित सीमाओं के भीतर ही अपने प्रतिष्ठानों एवं सामग्री का उपयोग करें।मुख्य नगरपालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने विभिन्न वार्डों में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आपने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें।जिससे नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाया जा सके।इस अवसर पर नायब तहसीलदार रणजीतसिंह चौहान, प्रभारी राजस्व निरीक्षक संजय परसाई, अमित परसाई, संजय पचौरी, हक्कूलाल परते,भूपेंद्र केवट सहित नगर परिषद के अमले के साथ जेसीबी मशीन एवं ट्रेक्टर ट्रालियां भी साथ थीं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा आयुष विभाग

जनप्रतिनिधियों को दिया योग दिवस पूर्वाभ्यास का आमंत्रण

बैतूल। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर आयुष विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर योग दिवस के पूर्वाभ्यास एवं आयोजन की जानकारी दी तथा उन्हें कार्यक्रम में

शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आयुष विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश राठौर, पार्षद वर्षा बारस्कार, तरुण ठाकरे एवं बंडू से सौजन्य भेंट कर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास की रूपरेखा से अवगत कराया। इस दौरान योग को जन-जन तक पहुंचाने और आयोजन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। सौजन्य भेंट के दौरान प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर, आयुर्वेद कम्पाउंडर प्रदीप सिंह भारद्वाज एवं कमलेश चौकीकर उपस्थित रहे। आयुष विभाग ने जनप्रतिनिधियों से योग दिवस कार्यक्रम में सहभागिता का आग्रह करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील की।

योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिदिन योग कक्षाओं का आयोजन - बैतूल। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शासन के द्वारा प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से 7 बजे तक जिला जनसंपर्क कार्यालय के सामने स्थित भवन में निशुल्क योग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित इन कक्षाओं में विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया जा रहा है। योग प्रशिक्षकों ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की गई है।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर निकली साइकिल रैली

बैतूल। जिला पंचायत द्वारा पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के तहत विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को ग्राम पंचायत कढ़ाई में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से फिट इंडिया अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपस्थित रही। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धुर्वे ने कहा कि साइकिल का नियमित उपयोग स्वास्थ्य संवर्धन के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस दौरान प्रतिभागियों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

योजना में बदलाव : प्रस्तावित स्थान मापदंडो के अनुरूप नहीं

क्रिकेट स्टेडियम के लिए नपा तलाश रही नई जमीन

बैतूल। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के लिए नगरपालिका ने नई जमीन की तलाश शुरू कर दी है। पहले स्टेडियम उत्कृष्ट स्कूल परिसर में बनाया जाना था, लेकिन यह स्थान तय मापदंडो के अनुरूप नहीं है। जिसकी वजह से नये स्थान की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्टेडियम निर्माण के लिए शहर के आसपास के कुछ जमीन देखें भी हैं। जिनमें से कोई एक जमीन फाइनल करके जल्द ही काम शुरू किए जाने की संभावना भी है। दरअसल आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई है। इसके पहले चरण में राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण होना है। क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 4.50 करोड़ रुपये की लागत से होना है। जिसके लिए टेंडर भी दिसंबर माह में हो चुका है। जल्द ही इसका भूमिपूजन करने की तैयारी भी थी, लेकिन इसी बीच यह बात सामने आई है कि

स्टेडियम के लिए जो जगह चुनी गई है, वह निर्धारित मापदंडों से काफी कम है। यही कारण है कि अब नई जगह की तलाश जोर-शोर से की जा रही है।

यह है स्टेडियम के लिए मानदंड- राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो मापदंड तय है, उनके अनुसार स्टेडियम का व्यास (डायमेंशन) 137 से 150 मीटर होना चाहिए। पिच की लंबाई 22 गज और चौड़ाई 10 मीटर हो। सेंटर से बाउंड्री की लंबाई 59 से 82 मीटर होनी चाहिए। इन मापदंडों के आधार पर बने स्टेडियमों में ही राष्ट्रीय स्तर के मैच किए जा सकते हैं। अभी क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो जगह चुनी गई है, वहां पर व्यास 90 मीटर ही आ रहा है। इसके अलावा दर्शक क्षमता भी मात्र 1000 लोगों की रहेगी। जाहिर है कि यह मापदंडों से बेहद कम है। इससे प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले इस स्टेडियम में बिल्कुल नहीं कराए जा सकेंगे।

दस हजार दर्शकों की क्षमता होगी- नगरपालिका का कहना है कि बैतूल में बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित स्टेडियम में मैदान का व्यास 137 मीटर से 150 मीटर तक रखा जाएगा, जबकि बाउंड्री की दूरी पिच के केंद्र से 65 से 90 मीटर के बीच होगी।

स्टेडियम के लिए हो चुके हैं टेंडर

उल्लेखनीय है कि स्टेडियम निर्माण के लिए टेंडर भी हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। जगह उपयुक्त होती तो अभी तक काम भी चालू हो चुका होता। इस क्रिकेट स्टेडियम में प्रशासनिक सह पवेलियन भवन, बाउंड्रीवॉल, फेसिंग रिटेनिंग वॉल, कल्वर्ट, एंट्री गेट, आरसीसी ड्रेनेज, शौचालय, रेस्ट रूम, आरसीसी रोड, पार्किंग एरिया, क्रिकेट फील्ड, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेडियम सीटिंग चेयर सहित अन्य निर्माण कार्य एवं व्यवस्था की जाएंगी। इधर शहर के क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि क्रिकेट स्टेडियम शहर के भीतर ही बने तो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी और खेल प्रेमी उसका उपयोग कर सकेंगे। नगर पालिका चूंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड को कढ़ाई में शिफ्ट कर ही रही है। वहां 10 एकड़ जमीन भी नपा की उपलब्ध है। इसलिए यदि वहां पर क्रिकेट स्टेडियम बना दिया जाएं तो यह सबसे बेहतरीन निर्णय होगा।

इनका कहना है -

उत्कृष्ट स्कूल मैदान में बनने वाला स्टेडियम मानकों अनुरूप काफी छोटा हो जाएगा। शहर में राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और नई जगह भी तलाश कर रहे हैं, ताकि यह स्टेडियम जिले के लिए बड़ी उपलब्ध हो सके।

- नवनीत पांडेय, सीएमओ नगरपालिका बैतूल।

स्थान बदलने से नई ड्राइंग और डिजाइन करना होगा तैयार

स्टेडियम का स्थान बदलने के कारण अब परियोजना की नई ड्राइंग और डिजाइन तैयार करनी होगी। वहीं परियोजना को शुरू होने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। वैसे खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा मांग की जा रही थी कि स्टेडियम का निर्माण मापदंडों के अनुरूप किया जाए, भले ही किसी अन्य जगह पर बनाना पड़े। यहीं वजह है कि गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड की जमीन को भी नगरपालिका विकल्प के रूप में देख सकती है। वर्तमान में इस स्थान पर शहर का कचरा डंप किया जा रहा है, लेकिन यदि ट्रेंचिंग ग्राउंड को प्रस्तावित ग्राम कढ़ाई में पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया जाता है तो नगरपालिका को शहर के भीतर ही करीब 10 एकड़ जमीन उपलब्ध हो सकती है।

आगजनी पीड़ितों के लिए प्रदीपन संस्था ने पहुंचाया एक माह का राशन और जरूरी सामग्री

बर्राढ़ाना के 20 प्रभावित परिवारों को मिला सहारा, राशन और वस्त्र बांटकर बांटा दर्द

बैतूल। भीमपुर विकासखंड के आदिवासी ग्राम मोहदा के बर्राढ़ाना में आगजनी की घटना से प्रभावित 20 परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदीपन संस्था ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से एक माह का राशन, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री वितरित की। संस्था का मानना है कि प्राकृतिक हो या मानव सृजित, हर प्रकार की आपदा में प्रभावित लोगों की मदद करना और समाज को आपदा प्रबंधन एवं बचाव के प्रति जागरूक बनाना उसका प्रमुख उद्देश्य है। उल्लेखनीय है कि विगत 2 मई को बर्राढ़ाना में भीषण आगजनी की घटना में 20 परिवारों के मकान जलकर खाक हो गए थे। घटना के बाद प्रभावित परिवारों को तत्काल सामाजिक और आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आर्थिक सहायता एवं हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया, वहीं गांव और आसपास के लोगों ने नमक, मिर्च, अनाज सहित अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाकर पीड़ितों के दुख को बांटने का प्रयास किया। जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी रसोई सामग्री और कपड़ों की व्यवस्था कर प्रभावित परिवारों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में योगदान दिया। प्रदीपन संस्था और मानव सेवा समिति ने भी तत्काल वस्त्र उपलब्ध कराए थे। प्रदीपन संस्था की डायरेक्टर ने बताया कि आगजनी जैसी घटनाओं में परिवार अचानक बेघर और

असहाय हो जाता है तथा उसे दोबारा गृहस्थी बसाने के लिए भोजन, पानी, कपड़े, दवाइयों, रसोई सामग्री, पानी संग्रहण एवं अनाज सुरक्षित रखने जैसी अनेक आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसी क्रम में 6 जून को प्राथमिक शाला मोहदा बर्राढ़ाना में राहत सामग्री का वितरण किया गया। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 15 किलो आटा, 2 किलो दाल, 10 किलो चावल, 2 किलो खाद्य तेल, शक्कर, चायपत्ती तथा सभी प्रकार के मसाले उपलब्ध कराए गए।

युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार

किसी और की तलाश में थे आरोपी, शक में दूसरे को पीटा

बैतूल। झल्लार थाना क्षेत्र में कथित मारपीट के बाद 19 वर्षीय युवक गोलू कासदेकर (कासदे) पुत्र विसराम कासदे की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, 5 जून की रात करीब 11.30 बजे गोलू चांदू पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि कुछ युवकों ने किसी अन्य विवाद के शक में गोलू के साथ लकड़ी और डंडों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी अन्य व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, लेकिन शक के आधार पर उन्होंने गोलू को निशाना बना लिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल गोलू को पहले जिला अस्पताल बैतूल लाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे नागपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए नागपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को वापस बैतूल

लाया गया। रविवार को जिला अस्पताल बैतूल में युवक का पोस्टमार्टम किया गया। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मौजूद रहे। परिजनों का आरोप है कि गोलू की मौत मारपीट के दौरान आई गंभीर चोटों के कारण हुई। उनका कहना है कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था और वह मजदूरी कर परिवार का सहारा था। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है।

झल्लार थाना प्रभारी वाहिद खान ने बताया कि युवक की मौत के बाद जिला अस्पताल में मर्ग कायम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्राप्त होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को विवाद की प्रारंभिक जानकारी मिली है और संभावित आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत किन चोटों के कारण हुई और घटना में शामिल लोगों की भूमिका क्या थी।

सांप के काटने पर समय बर्बाद ना करें, तुरंत मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं

● मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के छात्रों ने सीखा आपदा प्रबंधन

बैतूल। बाढ़, भूकंप, सांप के काटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए इसके प्रति जागरूक रहना ही बचाव है। ऐसी घटनाएं यकायक होती हैं और जिसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम की अंतर्गत बस और एमएसडब्ल्यू करने वाले छात्रों ने अपने असाइनमेंट के साथ-साथ आज आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा आपदा में होने वाले नुकसान को कैसे रोके और किस प्रकार से आपदा से बचने के उपाय साधारण नागरिक अपना सकता है और

इसे कैसे बचाव कर सकता है आदि संवेदनशील विषयों पर आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। जिला कमांडेंट होमगार्ड से सुनीता पंद्राम ने आपदा के प्रकार और बचाव जैसे बाढ़, भूकंप, सांप के काटने, आग लगने से लेकर विभिन्न आपदाओं से बचाव और राहत के विभिन्न तरीकों से अवगत कराते हुए कहा कि भूकंप का अहसास होने पर खुले मैदान की तरफ बढ़ें, इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों, होर्डिंग्स और पुल से तुरंत दूर हट जाएं। जमीन पर बैठ जाएं, किसी सुरक्षित और खुली जगह पर पहुंचकर जमीन पर बैठ जाएं। भूकंप के दौरान नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें, घबराकर ऊंची इमारत से कूदे नहीं। उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर शांत रहना और सही कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। घबराहट में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे जहर शरीर में तेजी से फैलता है। अगर आपने सांप को देखा है, तो उसका रंग या आकार याद रखें (या सुरक्षित दूरी से फोटो खींच लें)। इससे डॉक्टरों को इलाज में मदद मिलती है। याद रखें, सांप को पकडने या मारने में समय बर्बाद न करें। झाड़-फूंक के चक्कर समय बर्बाद करना जानलेवा हो सकता है। केवल डॉक्टर ही एंटी-वेनम से जान बचा सकते हैं। मरीज को एम्बुलेंस या किसी गाड़ी से ही अस्पताल ले जाएं, उन्हें पैदल न चलने दें। इस अवसर पर परामर्शदाता सुनील पवार, आशीष कोकने, राजू आठनेरे, मीनाक्षी मालवीय, प्रमोद जागरे सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर श्री वानखड़े की अध्यक्षता में एनसीओआरडी की बैठक सम्पन्न

दतिया (निप्र)। कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में विगत दिवस न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में एनसीओआरडी (नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खण्डेलवाल, वन मण्डलाधिकारी मोहम्मद माज, जिला आबकारी अधिकारी दतिया श्री बीएल दांगी सहित अन्य सदस्यगण, पुलिस, प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी की प्रवृत्तियों के बारे में आसूचना, सूचना का आदान-प्रदान किये जाने। जिले में अफीम, भांग आदि की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने, ऐसे प्रकरण जो क्रास-स्टेट संबंधी हो, उनकी जांच की प्रगति की निगरानी किये जाने। स्कूलों एवं कॉलेजों में नशीली दवाओं के दुरूपयोग विरोधी जागरूकता को बढ़ावा देने, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों और दवाओं के हानिकारक प्रभावों पर मादक फसलों की अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने। जिले में मादक फसलों की अवैध खेती से प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम लागू करने व जिले में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने आदि बिन्दुओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर श्री वानखड़े द्वारा बैठक में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बीरा में अवैध उर्वरक भंडारण पर कार्रवाई

124 बैग उर्वरक जब्त, बिना लाइसेंस भंडारण एवं विक्रय के मामले में प्राथमिकी दर्ज

शिवपुरी (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने समस्त एसडीएम को खाद्य की कालाबाजारी को लेकर सख्त निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम द्वारा निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। गत दिवस पिछोर एसडीएम श्रीमती ममता शाक्य ने ग्राम वीरा में अवैध उर्वरक भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही की है। एसडीएम पिछोर श्रीमती ममता शाक्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ब्रजमोहन (मुन्ना गुप्ता) पुत्र भैयालाल गुप्ता निवासी ग्राम बीरा की दुकान एवं गोदाम की जांच की गई। संबंधित व्यक्ति को दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु वह मौके पर उपस्थित नहीं हुआ तथा मोबाइल फोन बंद पाया गया।कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा पंचों की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुल 124 बैग उर्वरक भंडारित पाया गया, जिसमें यूरिया (एनएफएल कंपनी) 94 बैग, एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट अन्नदाता) 27 बैग एवं एनपीके (20:20:0:13) पीपीएल नवरत्न 3 बैग शामिल हैं।बिना लाइसेंस किया जा रहा था उर्वरक का भंडारण एवं विक्रयजांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना वैध उर्वरक अनुज्ञप्ति के उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।

सहायक कोषालय अधिकारी ने मां की स्मृति में किया पौधारोपण

अशोक नगर (निप्र)। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला कोषालय कार्यालय में पदस्थ सहायक कोषालय अधिकारी श्री अशोक राणा ने कलेक्ट्रेट परिसर मे मां की स्मृति में बरगद का पेड़ लगाया। यह पेड़ ऐसे स्थान पर लगाया जिसकी छाया का लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने बताया कि उनकी माता जी का स्वर्गवास 21 मई को हो जाने के कारण माँ की स्मृति मे एक पेड़ लगाया और जिले मे पदस्थापना तक वृक्ष की देख रेख करने की भी जिम्मेदारी ली।

आरोह-26 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को ध्यान एवं स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक

मुरैना (निप्र)। आरोह-26 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को खिलाड़ियों के लिए ध्यान, स्वास्थ्य एवं संतुलित जीवनशैली विषयक प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पद्मेश उपाध्याय भी उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 600 खिलाड़ियों ने सहभागिता की। अपर कलेक्टर श्री रावत ने खिलाड़ियों को ध्यान (मेडिटेशन) का अभ्यास कराया तथा हर्टफुलनेस पद्धति के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शारीरिक क्षमता के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के नियमित अभ्यास से एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है, जिससे खिलाड़ी अपने लक्ष्य पर बेहतर ढंग से केंद्रित रह पाते हैं। उन्होंने बताया कि देश-विदेश के अनेक सफल खिलाड़ी ध्यान एवं हर्टफुलनेस जैसी पद्धतियों को अपनाकर अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार कर रहे हैं।

उन्होंने खिलाड़ियों को संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम तथा सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह भी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पद्मेश उपाध्याय ने खिलाड़ियों को बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई मजबूती ग्रामीणों से सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील

दतिया (निप्र)। कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े ने शुक्रवार को ग्राम दुरसड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में नव निर्मित प्रसव केंद्र एवं पीएनसी यूनिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित महिलाओं, बच्चों एवं ग्रामीणों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री वानखड़े ने कहा कि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नव प्रारंभ किए गए प्रसव केंद्र एवं पीएनसी यूनिट से गर्भवती महिलाओं को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी, वहीं नवजात शिशुओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं एवं एएनएम को निर्देशित किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करें। साथ ही घर-घर जाकर इस नवीन स्वास्थ्य सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को इसकी जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब पात्र हितग्राहियों तक इनका लाभ समय पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वानखड़े ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं, उपलब्ध संसाधनों तथा उपचार संबंधी सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।

इस दौरान उन्होंने स्वयं अपना ब्लड शुगर परीक्षण भी कराया तथा स्वास्थ्य जांच एवं नियमित परीक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कलेक्टर श्री वानखड़े ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि शासन द्वारा जनसामान्य के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी नागरिक आगे आकर इन सेवाओं का लाभ लें तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

● अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, वैध परियोजनाओं को मिलेगा प्रशासनिक सहयोग

सस्ती और सुविधायुक्त कॉलोनियां विकसित करें: कलेक्टर

हर परिवार का घर का सपना पूरा हो

गुना (निप्र)। शहर का विकास केवल प्लॉट बेचने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्थित और सुविधायुक्त कॉलोनियां विकसित हों जहां आम नागरिकों को कम लागत में घर मिल सके और बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध हों। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने गुरुवार को जिले के कॉलोनाइजरों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का सपना अपना घर होने का होता है, इसलिए कॉलोनी विकास में लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी और शहर के सुनियोजित विकास को भी प्राथमिकता देनी होगी।कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुरूप विकसित कॉलोनियों को प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कॉलोनी नहीं, बेहतर जीवनशैली विकसित करें : कलेक्टर ने कहा कि भविष्य की कॉलोनियों में केवल सड़क, बिजली और पानी ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन से जुड़ी सेवाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। खाना बनाने, कपड़े धुलाई, साफ-सफाई, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत जैसी सेवाएं कॉलोनी स्तर पर उपलब्ध कराने के मॉडल विकसित किए जाएं, जिससे रहवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने पर जोर: बैठक में कलेक्टर ने आधुनिक एवं पर्यावरण हितैषी निर्माण तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने बताया कि भवनों में ऐसी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं जिनसे तापमान नियंत्रित रहे, ऊर्जा की बचत हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। कॉलोनाइजरों से नवाचार आधारित निर्माण को बढ़ावा देने की अपील भी की गई।

वैध कॉलोनियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी : कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वीकृत एवं वैध कॉलोनियों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे वैध परियोजनाओं में ही निवेश या मकान खरीदने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल अवैध कॉलोनियों की प्रवृत्ति को भी रोकने में मददगार होगी।

सिंगल विंडो सिस्टम से आसान होगी प्रक्रिया: बैठक में कॉलोनी विकास से जुड़ी अनुमतियों एवं विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि इसके तहत एक नोडल अधिकारी के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रक्रियाओं का समन्वय किया जाएगा, जिससे कॉलोनाइजरों को अनावश्यक देरी और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्वालियर ने दिया पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश

रमौआ जलाशय पर श्रमदान, आनंद पर्वत पर पौधरोपण और ई-वाहन रैली से जन-जन को किया जागरूक

ग्वालियर (निप्र)। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में सरकार की मंशा के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों और आम नागरिकों ने मिलकर ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन, ऊर्जा बचत और हरित विकास का प्रभावी संदेश जन-जन तक पहुँचाया।

रमौआ जलाशय पर श्रमदान से दिया जल संरक्षण का संदेश : दिन की शुरुआत रमौआ जलाशय पर व्यापक स्वच्छता अभियान से हुई। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस अभियान में सैकड़ों नागरिकों ने श्रमदान कर जलाशय के घाटों और आसपास फैले कचरे को हटाया। लोगों ने दस्ताने पहनकर पूजन सामग्री, पॉलीथिन, कपड़े और अन्य अपशिष्ट एकत्रित किए। अभियान के दौरान 6 से 7 डंपर कचरा हटाया गया। इस जन-अभियान से प्रभावित होकर स्थानीय ग्रामीण भी सफाई कार्य में शामिल हुए और भविष्य में जलाशय को स्वच्छ बनाए रखने तथा उसमें कचरा फेंकने वालों को रोकने का संकल्प लिया।

आनंद पर्वत पर पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाने का लिया संकल्प : इसके बाद आनंद पर्वत पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहर की बंजर पहाड़ियों को हरियाली से आच्छादित करने के संकल्प के साथ यहाँ प्रतीक स्वरूप 101 पौधे रोपे गए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव सहित अन्य अधिकारियों एवं नागरिकों ने पौधरोपण कर वर्षाकाल में होने वाले व्यापक वृक्षारोपण अभियान की सामूहिक तैयारी का संदेश दिया। साथ ही सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

अवैध परिवहन में संलिप्त 02 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

गुना (निप्र)। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को गुना शहर क्षेत्र में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खनिज अधिकारी श्री सचिन वर्मा ने बताया कि जांच के दौरान एम-सैंड का बिना रॉयल्टी के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गईं। जब्त वाहनों को कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षित रखा गया है। संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। कार्रवाई में प्रभारी खनिज निरीक्षक श्री विजय चक्रवर्ती एवं विभागीय अमले द्वारा की गई।

विश्व पर्यावरण दिवस पर मुरैना जिले में किया गया पैधारोपण

मुरैना (निप्र)। वश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, चंबल संभाग के संभागीय समन्वयक श्री धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया एवं जिला समन्वयक श्री सतीश सिंह तोमर के निर्देश तथा मुरैना विकासखंड के ब्लॉक समन्वयक श्री अनिल मोदी के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था 'मुरैना यूथ अकादमी' द्वारा ग्राम जेवरा खेड़ा, सेक्टर माता बसैया में पर्यावरण संरक्षण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें सामुदायिक स्वास्थय अधिकारी (सीएचओ) डॉ. विवेक शर्मा, संस्था प्रतिनिधि श्री संदीप सेंगर, सीएमसीएलडीपी अंतर्गत संचालित बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम की मेंटर श्रीमती सायरा जैन, आशा कार्यकर्ता श्रीमती कस्तूरी देवी, श्रीमती

ममता कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। पीजी कॉलेज में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भिण्ड विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने किया पौधारोपण

भिण्ड (निप्र)। विश्व पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिण्ड विधायक श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) श्री वी.आर. सिरसाम एवं रेंजर श्री वसंत शर्मा की उपस्थिति में करीब आधा सैकड़ा पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर डीएफओ श्री वी.आर. सिरसाम ने वनकर्मियों को पौधारोपण की वैज्ञानिक पद्धति की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि फलदार एवं अन्य पौधों के लिए लगभग 45 सेंटीमीटर गहराई तथा समान लंबाई-चौड़ाई का गड्ढा तैयार किया जाता है, जिससे पौधे का विकास बेहतर ढंग से हो सके। उन्होंने पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा एवं देखभाल के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। भिण्ड विधायक श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्ष ही सबसे बड़ा सहारा हैं। डीएफओ श्री सिरसाम ने कहा कि पौधारोपण करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनकी सुरक्षा और संरक्षण करना है।

एसडीएम चांचौड़ा ने खाद वितरण केंद्रों का किया निरीक्षण

गुना (निप्र)। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी चांचौड़ा श्री रवि मालवीय ने चाचौड़ा-बीनागंज स्थित मार्कफेड गोदाम, डबल लॉक केंद्र चाचौड़ा एवं सहकारी समिति पैंची के खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ई-टोकन आधारित खाद वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई। लंबित टोकनों एवं खाद वितरण की स्थिति का जायजा लेते हुए किसानों के लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। एसडीएम श्री मालवीय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित समय एवं नियमों के अनुसार खाद का वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार श्री मयंक खेमरिया, एसएडीओ श्री सिलावट एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।

स्व सहायता समूहों ने पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प,हर दीदी 5-5 पेड़ लगाएगी

अशोक नगर (निप्र)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश कुमार जैन के मार्गदर्शन में विश्व पर्यावरण दिवस अंतर्गत मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला अशोक नगर अंतर्गत समस्त पंचायतों में स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं एक पेड़ मां के नाम हेतु जनजागरूकता अभियान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान समूह सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे लगाए गए एवं लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने, जल संरक्षण करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

जनसेवा शिविर

शासन आपके द्वार, समाधान आपका अधिकार : शिकायतों का मौके पर कराया निराकरण

संपर्क अभियान शिविर में कलेक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं

दतिया (निप्र)। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित 'संपर्क अभियान' के अंतर्गत आज ग्राम दुरसड़ा में आयोजित वृहद जनसेवा शिविर में जिला कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े ने सहभागिता कर आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया। शिविर के दौरान कलेक्टर ने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने शिविर परिसर का भ्रमण कर विभिन्न विभागीय काउंटरों का अवलोकन किया तथा उपस्थित उपभोक्ताओं से चर्चा कर विद्युत सेवाओं एवं विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर श्री वानखड़े ने अपने संबोधन में कहा कि 'संपर्क अभियान का उद्देश्य केवल शिकायतों का निराकरण करना नहीं, बल्कि आमजन और प्रशासन के बीच संवाद, विश्वास एवं सहभागिता को मजबूत करना है।'

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे विद्युत विभाग द्वारा आयोजित ऐसे शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं एवं सुझावों को विभाग तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिजली शिक्षा, कृषि, उद्योग, रोजगार एवं आधुनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकता बन चुकी है। ऐसे में विद्युत संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने विद्युत चोरी के विरुद्ध जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि सफेद तार अथवा अन्य किसी भी माध्यम से अवैध विद्युत उपयोग कानूनन अपराध है तथा इससे विभाग एवं ईमानदार उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होता है। कलेक्टर ने बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना उपलब्ध है, वहां घरेलू विद्युत कनेक्शन मात्र 5 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में पात्र बीपीएल परिवार भी मात्र 5 रुपये में घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से वैध विद्युत कनेक्शन लेकर ही विद्युत उपयोग करने का आग्रह किया। जिन क्षेत्रों में स्थायी अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है, वहां अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर सुरक्षित एवं वैधानिक रूप से बिजली का उपयोग किया जाना चाहिए। शिविर में स्थापित स्मार्ट मीटर डेमो काउंटर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यहां श्री संदीप अग्रवाल द्वारा स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली, रियल टाइम ऊर्जा खपत की निगरानी, पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कलेक्टर महोदय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर विद्युत प्रबंधन एवं उपभोक्ता सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भीषण गर्मी एवं लगातार बढ़ते तापमान के बीच निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में जुटे लाइनमैन एवं मैदानी कर्मचारियों की कलेक्टर महोदय ने विशेष प्रशंसा की।

विदिशा के शिक्षक ने एक ही पेड़ पर उगा दिए 35 तरह के आम!

जापानी 'मियाजाकी' और 6 किलो वजन वाला 'ब्रूनाई किंग' भी लटक रहा

विदिशा (नप्र)। कहते हैं कि अगर कुछ नया सीखने की ललक और सही वैज्ञानिक सोच हो, तो मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। इसे सच कर दिखाया है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पमारिया गांव के रहने वाले शिक्षक और प्रगतिशील किसान बालकृष्ण विश्वकर्मा ने। उन्होंने अपने अनूठे नवाचारों और कड़े परिश्रम से पारंपरिक खेती को आधुनिकता का ऐसा रंग दिया है कि आज वे पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़े रोल मॉडल और प्रेरक उदाहरण बन चुके हैं।

बगीचे में महक रहा है दुनिया का सबसे महंगा 'मियाजाकी' आम

शिक्षक बालकृष्ण विश्वकर्मा ने अपने बगीचे में जापान की बेहद प्रसिद्ध और दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्मों में शुमार 'मियाजाकी' को सफलतापूर्वक तैयार किया है। अंतरराष्टीय बाजार में लाखों रुपये किलो तक बिकने वाले इस आम की एमपी के एक छोटे से गांव में सफल पैदावार होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

ग्राफ्टिंग कर किया जादू, एक पेड़ पर 35 किस्में!

शिक्षक की वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण उनके द्वारा अपनाई गई ग्राफ्टिंग (कलमकारी) तकनीक है। इस तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल से उन्होंने एक ही आम के पेड़ पर 35 अलग-अलग किस्में विकसित कर दी हैं। यानी एक ही पेड़ की अलग-अलग टहनियों पर अलग-अलग स्वाद और प्रजातियों के आम फल रहे हैं, जो कृषि विशेषज्ञों के लिए भी कौतूहल का विषय है।

आंवले के बाद अब आम में बिखेरा जलवा

यह पहली बार नहीं है जब बालकृष्ण विश्वकर्मा ने ऐसा कोई कमाल किया हो। इससे पहले वे इलाके में आंवले की उन्नत खेती का सफल प्रयोग कर चुके हैं, जिससे प्रेरणा लेकर क्षेत्र के कई अन्य किसानों ने भी अपनी आमदनी को बढ़ाया था। उनकी यह लगातार सफलता दर्शाती है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयोग से कृषि क्षेत्र में कितने असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उनकी इस उपलब्धि की कहानी एमपी शासन व जिला प्रशासन भी बयां कर रहा है। जेडी जनसंपर्क सोशल मीडिया ने भी उनके फोटो शेयर किए हैं।

आजीविका नहीं, नवाचार की प्रयोगशाला

बता दें कि बालकृष्ण विश्वकर्मा जैसे शिक्षक सह किसान यह साबित करते हैं कि जब शिक्षा, आधुनिक सोच और कड़ी मेहनत का संगम होता है, तो खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया या आजीविका नहीं रह जाती, बल्कि वह नवाचार की एक जीवंत प्रयोगशाला बन जाती है। उनके ये प्रयास न केवल स्थानीय किसानों को पारंपरिक ढर्रे से हटकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि भारतीय कृषि के भविष्य को भी एक नई और समृद्ध दिशा दे रहे हैं।

6 किलो का 'ब्रूनाई किंग' और 'अंगूर दाना' आम भी है मौजूद

शिक्षक बालकृष्ण का बगीचा इस समय दुर्लभ आमों का गढ़ बना हुआ है और दूर-दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। उनके बगीचे में जहां एक तरफ दुनिया का सबसे भारी माना जाने वाला 'ब्रूनाई किंग' आम आकर्षण का केंद्र है, जिसका वजन 6 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे छोटे आकार का 'अंगूर दाना' आम भी इसी बगीचे की शोभा बढ़ा रहा है।

नरेला में बारिश पूर्व तैयारियों की जमीनी हकीकत जांचने निकले मंत्री सारंग

पातरा नाले में मिट्टी डंप होने पर जताई नाराजगी, तत्काल शुरू कराया मिट्टी हटाने का कार्य

भोपाल (नप्र)। आगामी मानसून को देखते हुए नरेला विधानसभा क्षेत्र में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग रविवार सुबह स्वयं सड़कों पर उतरे और नरेला विधानसभा के प्रमुख नाले-नालियों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री श्री सारंग ने प्रभात चौराहा, महामाई की पुलिया, द्वारका नगर, भानपुर खंती सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति देखी और अधिकारियों को बरसात के पहले सफाई और मरम्मत करने के निर्देश दिए।

सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार- निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नाले-नालियों की सफाई कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मंत्री श्री सारंग ने नगरनिगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नाले-नालियों की पूरी तरह सफाई होना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, आम नागरिकों को बाढ़ जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जाए ताकि पानी की निकासी सुचारू बनी रहे।

पातरा नाले का किया विशेष निरीक्षण- दौरे के दौरान मंत्री श्री सारंग ने भोपाल शहर के सबसे बड़े पातरा नाले का भी निरीक्षण किया, जो नरेला विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पातरा नाला पूरे भोपाल शहर की जल निकासी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इसकी सफाई समय पर नहीं हुई तो बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

एनएचएआई के कार्य पर जताई नाराजगी- भानपुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने देखा कि एनएचएआई द्वारा निर्माणाधीन 10 लेन प्रोजेक्ट के कार्य के चलते पातरा नाले में बड़ी मात्रा में मिट्टी डंप की गई है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाले में मिट्टी डंप होने से पानी का प्रवाह बाधित होगा और इसका असर पूरे भोपाल शहर पर पड़ेगा। बारिश के समय यह स्थिति बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकती है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

स्कूटी सवार बदमाशों ने की हवाई फायरिंग

गाली-गलौज करते हुए कई राउंड फायर किए, भागते समय गिरी स्कूटी, सीसीटीवी आया सामने

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की अशोका कॉलोनी में शुक्रवार देर रात स्कूटी सवार दो बदमाशों ने सरेराह हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वारदात के बाद भागते समय बदमाशों की स्कूटी असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें पकड़ पाते उससे पहले ही दोनों मौके से फरार हो गए। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। जो रविवार को सामने आया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 10 बजे दो युवक स्कूटी से अशोका कॉलोनी की एक गली में पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने वहां पहुंचकर गाली-गलौज शुरू कर दी और इसके बाद हवा में कई राउंड फायर कर दिए। अचानक हुई गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि बदमाश किसी को डराने या इलाके में अपना प्रभाव दिखाने के इरादे से पहुंचे थे। हालांकि फायरिंग का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

भागते समय गिरी स्कूटी

फायरिंग के बाद दोनों बदमाश तेजी से वहां से भागने लगे। इसी दौरान उनकी स्कूटी फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसके बावजूद उन्होंने तुरंत स्कूटी उठाई और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। घटना की सूचना मिलते ही शाहजहानाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों युवकों की गतिविधियां कैद हुई हैं। फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

गाड़ियों के शीशे टूटे, तीन पर एफआईआर

शाजापुर में अवैध रेत खनन रोकने पहुंची खनिज विभाग की टीम पर पथराव

शाजापुर (नप्र)। मध्य प्रदेश में रेत माफिया बेखौफ हैं। शाजापुर में कार्रवाई के लिए पहुंची प्रशासन की टीम पर रेत माफियाओं ने पथराव किया है। इस हमले में कई सरकारी गाड़ी के कांच भी फूट गए हैं। इसके बाद रेत माफिया वहां से ट्रैक्टर लेकर भाग गए हैं।

जंगीखेड़ी गांव में हो रहा था खनन- दरअसल, कालापीपल क्षेत्र के जंगीखेड़ी गांव में खनिज विभाग के अधिकारियों पर पथराव हुआ। गांव में लंबे समय से अवैध खनन हो रही थी। मगर प्रशासन की टीम ने कभी यहां पहुंचकर कार्रवाई नहीं की है।

पार्वती नदी में अवैध खनन- बताया जा रहा है कि पार्वती नदी के किनारे अवैध उत्खन की शिकायत मिली थी। सूचना पर खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने टीम का विरोध किया और अचानक पत्थर फेंकने लगे। पत्थर शासकीय वाहन पर लगे, जिससे शीशे टूट गए। अधिकारी और कर्मचारी किसी तरह बच गए।

ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर फरार- हंगामे के बीच आरोपी ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर फरार हो गए। खनिज टीम ने मौके से रेत से भरा एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया। लेकिन पत्थरबाजी की वजह से बाकी मशीनों को पकड़ने की कार्रवाई बीच में रोकनी पड़ी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है।

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कालापीपल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीन लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। शुजालपुर एसडीओपी के अनुसार खनिज अमला वहां कार्रवाई करने पहुंची। ट्रैक्टर रोकने पर ग्रामीणों ने पथराव किया है। तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच जारी है।

इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर कार्रवाई करने गई टीम ही सुरक्षित नहीं है तो अवैध खन पर कैसे रोक लगेगी। मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी रेत माफिया खनिज विभाग की टीम पर हमला करते रहे हैं।

इंदौर में यातायात नियमों की अनदेखी भारी, 5 महीनें में 7 करोड़ का जुर्माना

हेलमेट अभियान धीमा, गलत पार्किंग, नंबर प्लेट गड़बड़ पर सख्ती

इंदौर। शहर की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस लगातार कड़ा रुख अपना रही है। इस साल के शुरुआती पांच महीनों के भीतर ही पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूलने का आंकड़ा 7 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया।

हालांकि, बीते चार महीनों के मुकाबले मई के महीने में पुलिस की कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भीषण गर्मी और सोशल मीडिया पर उठती आवाजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हेलमेट न पहनने वालों को थोड़ी राहत दी, जिसके कारण हेलमेट से जुड़े चालान आधे से भी कम रह गए। मई में पुलिस ने इस श्रेणी में केवल 12738 चालान ही बनाए। हेलमेट अभियान को थोड़ा धीमा करने के साथ ही यातायात पुलिस ने अपना पूरा ध्यान सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने वाले अन्य कारकों पर केंद्रित कर दिया।

मई तक 30,928 पर कार्रवाई

मई महीने में गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों, दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने वालों, लाल बत्ती पार करने वालों, विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों और गाड़ी चलाते समय दूरभाष पर बात करने वालों के खिलाफ विशेष कड़ाई बरती गई। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, तो मई 2026 में कुल 30928 वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिससे कुल 1 करोड़ 13 लाख 3 हजार 500 रुपए का शमन शुल्क एकत्रित हुआ। यह राशि अप्रैल 2026 के मुकाबले 58 लाख 86 हजार 750 रुपए कम रही, क्योंकि अप्रैल में पुलिस ने 47276 चालान काटकर रिकॉर्ड 1 करोड़ 71 लाख 90 हजार 250 रुपए का जुर्माना वसूला था।

इन गलतियों पर जुर्माना

मई के महीने में पुलिस ने विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों पर कार्रवाई की, जिसमें गलत तरीके से वाहन खड़े करने के 5297 मामले, नंबर प्लेट की गड़बड़ी के 3092 मामले, यातायात संकेतों की अनदेखी के 2244 मामले, विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने के 1500 मामले और वाहन चलाते समय दूरभाष के उपयोग के 1431 मामले शामिल रहे। इन सब के बावजूद, साल के पहले पांच महीनों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की संख्या सबसे अधिक रही और इस अवधि में कुल 1 लाख 52 हजार 175 चालान केवल इसी लापरवाही के लिए बनाए गए। यातायात विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और बार-बार गलती दोहराने वाले चालकों के वाहन चलाने के अनुज्ञा पत्र को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इतने सालों जुर्माने का आंकड़ा

यदि पिछले कुछ सालों के सरकारी खजाने में जमा हुए जुर्माने पर नजर डालें, तो साल 2023 में 070838400 रुपए, साल 2024 में 055710000 हजार रुपए और 2025 में 082888000 रुपए की वसूली की गई थी। वहीं इस साल 2026 में मई महीने तक ही यह राशि 072205200 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस साल महीनेवार हुई कार्रवाई को देखें तो जनवरी में 41752 चालान से 1 करोड़ 50 लाख 87 हजार 800 रुपए, फरवरी में 40676 चालान से 1 करोड़ 37 लाख 64 हजार 900 रुपए, मार्च में 43921 चालान से 1 करोड़ 48 लाख 58 हजार 750 रुपए जमा किए गए, जो अप्रैल और मई की सख्त कार्रवाई के साथ बढ़ते हुए इस नए स्तर पर पहुंचे हैं।

कही-सुनी

बीजेपी के लिए खतरे की घंटी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायतों के उप चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, उसे भाजपा के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, फिर भी नगरीय निकाय के पांच अध्यक्षों के लिए हुए उप चुनाव में कांग्रेस ने दो पर कब्ज़ा जमा लिया। पार्षदों के 71 पदों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को 39 सीटें मिली। कांग्रेस के 30 पार्षद जीतकर आ गए। पंचायतों में गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए, लेकिन पंचायतों के नतीजों से कांग्रेस गदगद है। नगरीय निकाय के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर में ही कांग्रेस पार्षद की जीत हो गई। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में भले बीजेपी का अध्यक्ष चुनकर आ गया, पर बहुमत कांग्रेस पार्षदों का है। बताते हैं नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के कई नेता और मंत्री लगे थे, इसके बाद भी बीजेपी को क्लीन स्वीप न मिलना, सोचनीय है। राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार को ढ़ाई साल हो गए हैं। 2023 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और नगरीय निकाय और जिला पंचायतों-जनपदों में भी दबदबा बनाया। राज्य के करीब-करीब सभी शहरी निकायों और पंचायतों में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आमतौर पर उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी की ही जीत होती है। लोग सत्ता की विपरीत धारा में बहते नजर नहीं आते, पर नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे गांव-गांव पहुंचकर लोगों के दुख -दर्द के सहभागी बन रहे हैं, पर नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे जिस तरह आएं हैं, उससे लग रहा है कि सरकार को काम करने का तौर-तरीका बदलना होगा और लोगों की समस्याओं के इलाज के लिए जल्दी ही कदम उठाना पड़ेगा।

पवन साय का बढ़ेगा कद

छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन महामंत्री पवन साय के प्रमोशन की चर्चा है। कहते हैं कि पवन साय को जल्द ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाकर कम से कम दो राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में पवन साय के प्रभार वाले इलाके में बीजेपी का परफार्मेंस काफी अच्छा रहा। इसका पुरस्कार पवन साय को मिलेगा ही। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पवन साय के संगठन महामंत्री के कार्यकाल में 2023 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य में सरकार बनाने में सफल रही। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भी बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। संगठन महामंत्री के तौर पर पवन साय ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को नई ऊंचाई पर पहुँचाया, इस कारण उनका कद बढ़ना तय माना जा रहा है।

मंत्री जी की चंदा उगाही चर्चा में

राज्य के एक मंत्री जी की चंदा उगाही आज कल सुर्ख़ियों में है। कहते हैं मंत्री जी ने अपने बच्चे की शादी की तो अपने विभाग के अफसरों को टारगेट दे दिया, फिर अपने इलाके में एक धार्मिक आयोजन करवाया तो फिर लक्ष्य दे दिया। बताते हैं कि धार्मिक आयोजन के लिए विभाग के जिला अधिकारियों को 10-10 लाख तक धन की व्यवस्था का फरमान दिया था। जिला अधिकारियों ने अपना सिर दर्द मातहत अफसरों पर डाल दिया। इन मंत्री जी के बारे में चर्चा है कि वे 40 फीसदी तक कमीशन लिए बिना कोई विभागीय टेंडर और अन्य काम की मंजूरी नहीं देते। मंत्री जी के कमीशन प्रेम से विभाग का भट्टा बैठा जा रहा है और जनता परेशान है। वैसे जब भी मंत्रिमंडल में फेरबदल का हल्ला शुरू होता है, हटाए जाने वालों में इन मंत्री जी का नाम उसमें शामिल रहता है।

मजबूत पकड़ वाले कलेक्टर साहब

कहते हैं कि राज्य के एक कलेक्टर साहब से एक सांसद और एक विधायक भारी नाराज हैं और कलेक्टर को हटाने के लिए सांसद और विधायक जी पूरा जोर भी लगा रहे हैं, पर कलेक्टर साहब हैं कि अंगद के पांव की तरह जमे हैं। खबर है कि कलेक्टर साहब सांसद और विधायक जी की बैठकों में भाग नहीं लेते, वे अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। बैठकों में कलेक्टर साहब को गैरहाजिर पाकर सांसद और विधायक जी अपना भड़ास निकालते हैं। बताते हैं कलेक्टर को हटवाने के लिए सांसद और विधायक जी ने भाजपा संगठन से एप्रोच भी किया है, पर अब तक बात बनी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि कलेक्टर साहब को राज्य के एक मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हल्ला है कि कलेक्टर साहब का राजनीतिक आधार काफी मजबूत है। इस कारण सांसद और विधायक महोदय की नाराजगी के बावजूद कलेक्टर साहब बड़े जिले में राज कर रहे हैं।

प्रशासनिक फेरबदल से खफा मंत्री

कहते हैं पिछले महीने हुए व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से राज्य के कुछ मंत्री खफा हैं और मुख्यमंत्री के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई है। बताते हैं प्रशासनिक फेरबदल करने से पहले मंत्रियों से न तो पूछा गया और न ही उनकी राय ली गई। खबर है कि कुछ अफसरों ने लिस्ट बनाई और मुख्यमंत्री से मंजूरी ले ली। बताते हैं कि कुछ मंत्रियों के विभागों में ऐसे अफसरों की पोस्टिंग कर दी हैं, जिन्हें वे पसंद नहीं करते। अब मंत्री और अफसरों में टकराव शुरू हो गया है। एक मंत्री के पसंदीदा सचिव को उनके विभाग से हटा दिया गया। इससे मंत्री बड़े नाराज बताए जाते हैं। एक मंत्री की अपने विभागाध्यक्ष से बढ़िया तालमेल बैठ गया था। अब उस विभाग में ऐसे अफसर को सचिव के तौर पर पदस्थ कर दिया गया है, जो विभागाध्यक्ष पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। इससे मंत्री जी का काम अटक सा गया है। इससे मंत्री जी बड़े दुखी बताए जाते हैं।